चिंतन

कुंभ भगदड़ की जांच करके दोषी पर हो सख्त कार्रवाई

किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि ऐसे दुर्घटना फिर जाएं, ताकि दोबारा उसी तरह के हालात पैदा न हों। मगर धार्मिक स्थलों पर या ऐसे आयोजनों में जमा होने वाली भीड़ और उसके प्रबंधन को लेकर अक्सर इस हद तक लापरवाही बरती जाती है कि बार-बार भगदड़ की वजह से लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक के बाद एक हो रहे ऐसे हादसों का सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी घटना हो जाने के बाद न तो किसी को दोषी ठहराया जाता है और न ही कोई कार्रवाई होती है और जान से हाथ धो बैठता है बेचारा आम आदमी। कौन भूला होगा हाथरस के हादसे को, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। अभी वो दिमाग से उतरा भी नहीं था कि प्रयागराज के संगम तट पर लगे कुंभ में अचानक भगदड़ मच गई और 35 से 40 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने अभी 20 लोगों के मरने की पुष्टि की है। महाकुंभ में संगम तट पर बुधवार की रात करीब डेढ़ बजे भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या' पर हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आए थे। भीड़ में धक्का-मुक्की हो गई। जो लोग पहले ही संगम में स्नान कर चुके थे, उनके वहां से निकलने के लिए जगह नहीं थी। हद तो यह भी थी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने के बाद लोग सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। न कोई बताने वाला था कि लोग किधर जाएं। कोई नक्शा या संकेत वगैरह वहां नहीं लगा था। अब सवाल यह है कि जब हादसा हुआ तब सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी कहां थे। ऐसी भगदड़ को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। वैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ मेला परिसर को राज्य का 76वां जिला ही घोषित कर रखा है। करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसे महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई हैं और सुरक्षा बलों के 60 हजार जवान तैनात हैं। हर थाने में साइबर डेस्क है। इतना ही नहीं, दो साइबर थाने भी अलग से बनाए गए हैं। सिविल पुलिस, पीएसी, एनएसजी, एसटीएफ, होमगार्ड, डिफेंस और एनजीओ को मिलाकर मेले में सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जिनमें एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेले में एआई युक्त कैमरे लगे हैं जो लोगों की गिनती करते हैं। अगर किसी इलाके में 2 हजार लोगों के खड़े होने की जगह है तो 1,800 लोग होते ही संबंधित अफसर को जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, 100 फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहीं, ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। पानी के अंदर की सुरक्षा के लिए पहली बार नदी के अंदर 8 किलोमीटर तक डीप बैरिकेडिंग की गई है। इसके बावजूद यह हादसा हो गया। इससे साफ है कि जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती तो ऐसा हादसा होना संभव ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे जांच तो होगी, लेकिन ऐसा न हो कि हमेशा की तरह भीड़ को जिम्मेदार ठहराकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, जैसा अब तक होता आया है। अगर भगदड़ मामलों में सख्ती दिखाई गई होती तो शायद आज ये हादसा न होता। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी सरकार दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

राहत और सुधारों का होगा बजट

उम्मीद
डॉ.जयंतीलाल भंडारी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां पूर्ण बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2025-26 का बजट एक ऐसा ऐतिहासिक बजट होगा, जिसमें खपत और व्यय बढ़ाकर घटी हुई विकास दर बढ़ाने, गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ आर्थिक सुधारों के साथ सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान दिखाई देंगे। वित्तमंत्री चालू वित्त वर्ष में जो पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है, उसे आगामी बजट में 4 फीसदी के स्तर पर पहुंचाते हुए अर्थव्यवस्था को धीमी विकास की मार से उबारने की रणनीति के साथ भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकेंगी।

इन दिनों पूरे देश की निगाहें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट की ओर लगी हुई हैं। सीतारमण का यह लगातार सातवां पूर्ण बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2025-26 का बजट एक ऐसा ऐतिहासिक बजट होगा, जिसमें खपत और व्यय बढ़ाकर घटी हुई विकास दर बढ़ाने, गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ आर्थिक सुधारों के साथ सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान दिखाई देंगे। वित्तमंत्री चालू वित्त वर्ष में जो पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है, उसे आगामी बजट में 4 फीसदी के स्तर पर पहुंचाते हुए अर्थव्यवस्था को धीमी विकास की मार से उबारने की रणनीति के साथ भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकेंगी। नए बजट के माध्यम से वित्तमंत्री आर्थिक डगर पर अटके पड़े सुधारों को आगे बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्री से अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर बुनियादी रणनीतियां प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगी।

इसके साथ-साथ वित्तमंत्री राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 फीसदी के स्तर पर रखते हुए खजाने को मजबूत करने की डगर पर भी आगे बढ़ेंगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खपत और व्यय में कमी से विकास दर घट गई है। मध्यम वर्ग के निजी उपभोग में कमी आई है। वैश्विक परिदृश्य पर जो सैन्य संघर्ष और आर्थिक गुटबाजी की चुनौतियां हैं, ये कोविड-19 से भी ज्यादा वैश्विक जीडीपी का नुकसान कर सकती हैं। डोनॉल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी नई आर्थिक रणनीति से दुनिया के आर्थिक गणित बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब कारणों से वैश्विक व्यापार और वैश्विक विकास दर में गिरावट आएगी। इन चुनौतियों के बावजूद इस समय वित्तमंत्री सीतारमण की मुट्ठियों में विभिन्न वर्गों को राहत देने और विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रभावी आवंटन हेतु कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। विगत एक दशक से आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हुई है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण करीब 16 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16 फीसदी से भी ज्यादा है। इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान भी कर संग्रह में भारी वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद है कि वित्तमंत्री आगामी बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को केंद्रित करते हुए दिखाई दे सकती हैं। बजट में वित्तमंत्री रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसान सम्मान निधि बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी

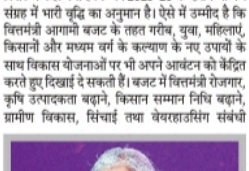

प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन, पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाने, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, स्वच्छ ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। आगामी बजट में वित्तमंत्री युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों से सजाते हुए दिखाई दे सकती है।

वित्तमंत्री सीतारमण नए बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने, पीएम किसान सम्मान राशि बढ़ाने, खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि वित्तमंत्री तेज रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित कर सकती हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) को मजबूत बनाने के लिए विशेष फंड बनाने, विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान तथा रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन दिखाई दे सकता है। इस समय चीन, पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी बाहरी सुरक्षा को खतरे बढ़े हैं, ऐसे में सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक धन की जरूरत स्पष्ट दिखाई दे रही है। चूंकि देश के विकास का इंजिन कहे जाने मध्यम वर्ग की मुट्ठियों में धन की कमी के कारण उनके निजी उपभोग पर होने वाले खर्च में गिरावट से विकास दर प्रभावित हो रही है।

ऐसे में आगामी बजट में खपत बढ़ाने के मद्देनजर मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बनाकर खर्चों और सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश उभर कर दिखाई दे सकती है। वित्तमंत्री सीतारमण मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहतों से लाभांवित कर सकती हैं। आयकर के नए टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री की जा सकती है। वित्तमंत्री आगामी बजट के माध्यम से टैक्स में कटौती और वित्तीय प्रोत्साहनों से आयकरदाता और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। वित्तमंत्री कर सुधारों की डगर पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वित्तमंत्री आयकर सुधारों के तहत वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में नया आयकर कानून पेश कर सकती हैं। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आसान, सरल और समझने योग्य बनाना है। नया आयकर कानून मौजूदा कानून में सिर्फ संशोधन नहीं होगा, बल्कि पूर्णतया एक नया कानून होगा। इसके तहत अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। कर विवादों को कम किया जाएगा। टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाया जाएगा।

हम उम्मीद करें कि एक फरवरी को वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला वर्ष 2025-26 का बजट आर्थिक कल्याण, आर्थिक सुधारों और तेज विकास को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट होगा। यह एक ऐसा बजट भी होगा, जिसमें वित्तमंत्री 2025-26 के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने के लक्ष्य के मद्देनजर राजकोषीय अनुशासन के पालन करते हुए भी दिखाई देंगी।

(लेखक स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

सारा संसार

कालाक्षी अम्मन मंदिर दिव्य देवी कामाक्षी को समर्पित है, जिन्हें प्रेम, प्रज्ञान क्षमता और ललित की हिंदू देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। पीठाकामाक्षी अम्मन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, माना जाता है इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी।

विमर्श
विकास खितौलिया

दिल्ली चुनाव में महिलाओं को फायदा होना निश्चित

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख दलों ने महिलाओं को नकद राशि, मुफ्त सफर और सस्ते भोजन सहित कई घोषणाएं की हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस चुनाव में सरकार किसी भी दल की बने, दिल्ली की महिलाओं को फायदा होना निश्चित है। दिल्ली में 27 साल से सत्ता का वनवास झेल रही भाजपा ने दिल्लीवालों के लिए मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा दी। भाजपा के इस कदम को आम आदमी पार्टी की घोषणाओं की काट के रूप में देखा जा रहा है। आप और भाजपा के अलावा कांग्रेस भी कई घोषणाएं कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया, उसके बावजूद चुनाव के बाद इसे 2100 प्रतिमाह करने का वादा आप सरकार कर चुकी है। बात करें पंजाब की तो इस तरह की योजना आप सरकार ने वहां भी लागू की थी, परन्तु करीब ढाई साल से ज्यादा का समय सरकार को बने हो गया है, यह योजना सिर्फ कागजों पर है। वहीं, भाजपा ने मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21 हजार रुपये देने और साथ ही महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वह इस योजना को लागू कर चुकी है। परंतु हकीकत यह है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहां भाजपा एवं एनडीए की सरकार है वहां भी इस योजना का कोई भी नामो निशान नहीं है। फिर कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है, प्यारी दीदी के नाम से योजना लागू की जिसके अंतर्गत दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया और पार्टी ने दावा भी किया कि इस योजना को सत्ता में आते ही लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली का कुल बजट लगभग 75 हजार करोड़ का है। अगर सत्ता में आने वाला कोई भी दल अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करेगा तो इसका लेप्ट करीब 35 से 40 हजार करोड़ राशि की जरूरत होगी। इससे साफ है कि ऐसी घोषणाएं किसी भी राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होंगी। एक तरफ देखा जाए तो जनता को सीधे धन ट्रांसफर कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। राजधानी में लगभग 60 लाख से अधिक महिलाएं हैं। सत्ता में आने वाला कोई भी दल यदि प्रतिमाह प्रत्येक महिला को 2000 रुपये भी देता है तो उसके लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये लगेंगे, जिसे भारत के अधिकांश अर्थशास्त्री ठीक नहीं मानते हैं। कोई भी सरकार अधिकांश राशि अपने घोषणा पत्र के अनुसार जनता में बांट देगी तो वह विकास के कार्य कैसे करेगी? अस्पताल, सड़क, स्कूल, स्टेडियम, पार्क कैसे बनेंगे? जो पहले से बना है उसकी मरम्मत, बुजुर्गों एवं विकलांगों को पेंशन वेतन आदि दे पाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। जनता को पैसा देना और लोकलुभावन वादे कर चुनाव जीतना लघु अवधि के कार्य हैं, जबकि आईआईटी, आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थान खोलना, उद्योग स्थापित करना, रोजगार देना यह दीर्घ अवधि तक नागरिक को सक्षम बनाने वाले कार्य हैं। सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, वह कितने लोगों को यह राशि देगी, जो जरूरतमंद है उनको देगी या सबको देगी। जैसा कि झुग्गी की महिला और एक कामकाजी महिला की जरूरत में अंतर है। हालांकि, राजनीतिक दलों के वादे जनता को तुरंत आकर्षित करते हैं और लोग इन बातों में आकर मतदान भी करते हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर ठीक नहीं है। (लेखक विश्लेषक)

सिया राम मय सब जग जानी

संकलित
दर्शन

हमारे वेद कहते हैं- सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया... अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों। वहां कोई, वर्ण, जाति, समूह और पक्ष-विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले यह सूत्र दे दिया था-वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। संपूर्ण विश्व के लोगों के सुख और स्वास्थ्य की कामना भारतीय दर्शन का मूल है। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जीव मात्र के हित की इच्छा रखना ही सनातनी परिचय है। मैं राम कथा गाता हूं। राम राज के मूल में भी सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की ही भावना है। भगवान श्रीराम ने सेतु बनाया। आज पूरे विश्व में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु बनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें भी राम तत्व होगा, वह केवल जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की नहीं। सत्य, प्रेम और करुणा प्रमुख राम तत्व हैं। जिसमें ये तत्व होंगे, वह वंचितों तक पहुंचेगा। राम समाज के वंचित लोगों के पास स्वयं चलकर गए। केवट, शबरी, अहिल्या के प्रसंग इसके प्रमाण हैं। आज समाज की एक बड़ी जरूरत है कि सक्षम लोग वंचित लोगों तक, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक स्वयं चल कर पहुंचें। मानस में नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। शबरी के सामने गई गई नौ प्रकार की भक्ति में गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति पूरे संसार को ब्रह्ममय मानना-देखना बताई है- 'सातवं सम मोहि मय जग देखा।' जब हम पूरे संसार को ब्रह्ममय देखेंगे, महसूस करेंगे तो किसी के भी दोष दिखाई नहीं देंगे।

ब्रह्माजी को दंड देने के लिए प्रकट हुए थे कालभैरव

संकलित
प्रेरणा

शिवजी के 19 अवतारों में से एक है कालभैरव। भैरव अवतार से जुड़ी कई अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं में ब्रह्माजी को दंड देने के लिए शिवजी के क्रोध से कालभैरव प्रकट हुए थे। कालभैरव की उत्पत्ति से जुड़ी सृष्टि की शुरुआत के समय की बहुत प्रचलित कथा है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बन गई। उस समय शिवलिंग प्रकट हुआ और शिव जी ने इन दोनों का विवाद शांत किया। उसी समय वहां एक विशाल पुरुष की आकृति प्रकट हुई। ये आकृति शिवजी का ही एक रूप थी। शिव जी ने उससे कहा कि तुम काल के समान हो और भीषण हो। इसी वजह से तुम्हारा नाम कालभैरव होगा। पंचमुखी ब्रह्मा जी बार-बार खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कालभैरव ने ब्रह्माजी का एक सिर काट दिया था। इस घटना के बाद से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। शिव जी ने कालभैरव को काशी का नगरपाल बना दिया। कालभैरव की पत्नी भैरवी देवी पार्वती की अवतार हैं। कालभैरव की पूजा में शराब (मदिरा), तामसिक खाना खासतौर पर चढ़ाया जाता है। दरअसल, कालभैरव हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले देवता हैं। इनकी पूजा करते समय भक्त नशे की चीजें चढ़ाकर अपनी बुराइयां छोड़ने का संकल्प लेता है। जो लोग इस संकल्प को निभाते हैं, उन्हें भैरव की विशेष कृपा मिलती है।

अंतर्मन

आज की पाती

सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों

मीडिया की माने तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में एक नया मोड़ आ गया है। यहां पहुंचे संतों और महंतों ने एक साथ मिलकर सरकार से सनातन बोर्ड बनाने और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी के नेतृत्व में संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि वे महाकुंभ छोड़कर तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जूना अखाड़े के महंत स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि, आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरि आदि सभी ने एक स्वर में सनातन बोर्ड गठन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। अब सरकार के फैसले का इंतजार है।

- प्रवीण दुबे, महासमुंद

ट्रेंड

महाकुंभ हादसे से व्यथित

महाकुंभ में हुए दुःखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूँ। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

भगदड़ की घटना दुःखद

प्रयागराज की संगम स्थली पर, महाकुम्भ में हुई भगदड़ में, जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है व घायल हुये हैं। यह घटना अति-दुःखद व चिन्तनीय। ऐसे समय में घुमटन पीड़ितों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, मेरी यही कामना है।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

ईमानदारी का सर्टिफिकेट

जनता ने शीला जी की कांग्रेस सरकार को पूरी दिल्ली को बदलते देखा है। ईमानदार को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती - जो बेईमान होते हैं वो ही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

शेयर बाजार का मिथक

शेयर बाजार का मूल्यांकन एक मिथक है। एक ऐसी बारूदी जिसे हर कोई पलट सकता है। इसका कंपनियों की कमाई की वास्तविकताओं से कोई लेना-देना नहीं है..।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

किम का परमाणु क्षमता को मजबूत करने का आव्हान

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री बनाने वाले एक संयंत्र का निरीक्षण किया और देश की परमाणु क्षमता को मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के बाद उत्तर कोरिया देश की परमाणु क्षमता को मजबूत करने का आह्वान कर अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किम के परमाणु सामग्री बनाने वाले संयंत्र में जाने से उत्तर कोरिया के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार पर निरंतर जोर देने का संकेत मिलता है। ट्रंप ने हालांकि कहा है कि वह कूटनीति को फिर से शुरू करने के लिए किम से बात करने को तैयार हैं। सरकारी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) की खबर के अनुसार, किम ने परमाणु सामग्री उत्पादन संयंत्र और परमाणु हथियार संस्थान जाकर निरीक्षण किया। खबर में यह नहीं बताया गया कि वे ठीक कहां स्थित हैं, लेकिन किम की यात्रा की उत्तर कोरियाई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि उन्होंने संभवतः यूरेनियम-संवर्धन केंद्र का दौरा किया था, जहां वह पिछले सितंबर में गए थे। केसीएनए की खबर के अनुसार किम ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष परमाणु सामग्री के उत्पादन में 'अद्भुत' प्रदर्शन किया है और देश की परमाणु क्षमता को मजबूत करने के लिए इस वर्ष उत्पादन को और बढ़ाने की जरूरत है।

ऑफ बीट

पहले की तुलना में ज्यादा पैदा हो रहे जुड़वां बच्चे

दुनियाभर में महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। जन्म दर में इस गिरावट के बावजूद, आज जुड़वां और एक साथ तीन बच्चों के जन्म के मामले पहले की तुलना में काफी बढ़े हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है - और शोध से जुड़वां बच्चों की दरों में निरंतर वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले वर्षों में, जुड़वां बच्चों के जन्म की दरें समग्र जन्म दरों के अनुरूप कम हुई हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। अधिक उम्र में गर्भधारण तथा प्रजनन उपचारों का अधिक उपयोग जैसे सामाजिक कारक इसके प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। हालांकि एक समय में एक बच्चे की तुलना में कई बच्चे पैदा होना कम आम बात है, लेकिन कई बच्चे पैदा होना मानव प्रजनन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लगभग हर 60 गर्भधारण में से एक में कई बच्चे पैदा होते हैं - चाहे वह दो, तीन या छह बच्चे हों। जुड़वां बच्चे तब होते हैं जब दो अलग-अलग अंडे एक ही समय में निषेचित (फर्टिलाइज) होते हैं, या जब एक निषेचित अंडा दो भागों में विभाजित हो जाता है। 'हाइपर-ओव्यूलेशन' के परिणामस्वरूप भी कई बच्चे पैदा हो सकते हैं - जब एक ही चक्र में एक से अधिक अंडे निकलते हैं। हालांकि बहुत दुर्लभ 'हाइपर-ओव्यूलेशन' यानी 'हाइपर-ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसीज' के कारण तीन शिशुओं से लेकर नौ शिशुओं तक का जन्म हो सकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान
1936

भीड़ प्रबंधन

प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ बहुत दुखद और विचारणीय है। यह और भी अफसोस की बात है कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन पहले से ही बहुत चाक-चौबंद था, फिर भी हादसा हो गया। पिछले कुम्भ 2013 में भी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची थी, पर वह भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस बार संगम तट पर हुई है। शायद प्रशासन सुबह के भव्य अमृत स्नान को सुगम बनाने के लिए तैयार हो रहा होगा, पर लगभग आधी रात के समय ही भीड़ उमड़ पड़ी और उससे बचाव का मौका हाथ से निकल गया। बेशक, प्रशासन अपनी आंतरिक जांच में अपनी खामियों पर गौर करेगा और उसे भीड़ प्रबंधन से जुड़ी कमियां नजर आएंगी। बेशक, लोग 1954 के कुम्भ को याद कर रहे होंगे, जब भगदड़ में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। उस कुम्भ से भी प्रशासन ने खूब सबक सीखे और कुम्भ आयोजनों को सुरक्षित और सुगम बनाया था। बेशक, प्रशासन के कुशल योजनाकारों को फिर एक बार अपनी योजनाओं के वृहद पटल पर लौटना होगा।

हमें बेहिचक स्वीकार करना चाहिए कि भीड़ अब हमारे लिए एक प्राथमिक समस्या बनती जा रही है। 1954 के कुम्भ के समय देश की आबादी 40 करोड़ भी नहीं थी और आज 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। भीड़ की समस्या केवल कुम्भ जैसे विशाल आयोजनों में नहीं हो रही है, लगभग हर शहर भीड़ से अक्सर ग्रस्त होने लगा है। ध्यान देने की बात है कि अपने देश में नौ से ज्यादा ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 70 लाख से भी ज्यादा है। लगभग 46 शहर ऐसे हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन शहरों के पास ऐसे मैदान भी नहीं हैं, जहां पांच लाख की भीड़ को एक जगह संभाल लिया जाए। मतलब, वास्तव में हमारे शहर बड़े आयोजनों के लिए तैयार नहीं हैं, इसका सीधा सा संकेत है कि किसी भी आयोजन में आने के लिए लोगों का आह्वान करना खतरे से खाली नहीं है।

बढ़ती भीड़ की समस्या केवल महाकुम्भ जैसे विशाल आयोजनों में ही नहीं हो रही है। लगभग हर बड़ा शहर अब भीड़ से अक्सर ग्रस्त रहने लगा है।

आबादी ऐसे बढ़ रही है कि हर शहर में आपको कुछ स्थान ऐसे मिल जाएंगे, जहां अक्सर भगदड़ की स्थिति बनती है। विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर गौर करने की जरूरत है। चूंकि स्टेशनों पर बड़ी आबादी के लिए सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, तो अक्सर लोगों को प्लेटफॉर्म पर बैठे-लेटे देखा जाता है। क्या हम सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं और उस हिसाब से सुविधाएं विकसित करने में कमी कर रहे हैं?

हमें बढ़ती भीड़ के विभिन्न पहलुओं से वाकिफ रहना होगा। प्रयागराज महाकुम्भ को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। क्या विशिष्ट अतिथियों और उनके संगे-संबंधियों की वजह से मेला प्रशासन किसी तरह के दबाव में है? क्या आम लोगों या यात्रियों के लिए सहज उपलब्ध सुविधाओं की कमी है? क्या भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ या श्रद्धालुओं का एक निश्चित कोटा बनाना पड़ेगा? ये ऐसे सामान्य सवाल हैं, जिन पर प्रशासन अवश्य विचार कर रहा होगा। प्रयाग के हादसे के बाद प्रशासन अपने इंतजाम दुरुस्त करेगा ही, किंतु आम लोगों को भी हमेशा के लिए सावधान हो जाना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कदम-कदम पर अनुशासन और संयम रखने की जरूरत है, पर क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? निस्संदेह, भीड़ की स्थितियों से बचने के लिए एक राष्ट्रीय व्यवहार संहिता बनाने और लागू करने की जरूरत अब और बढ़ गई है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 जनवरी, 1950

हमारा गणतंत्र

२६ जनवरी, १९५० को सवा दस बजे सुबह भारत की स्वातंत्र्य-साधना अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में कृतकार्य हो गई। यद्यपि १५ अगस्त, १९४७ को ही भारत स्वतन्त्र हो चुका था, किन्तु २६ जनवरी के ऐतिहासिक दिन का विशेष महत्व है। अब राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वतन्त्र भारत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पथ-प्रदर्शन में नवनिर्मित विधान को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया है और इसका एकमात्र उद्देश्य भारत की सर्वतोन्मुखी उन्नति, शांति तथा समृद्धि और साथ ही विश्व-शांति में योग देना है। ३१ लोधों की गड़गड़ाहट के साथ जब राजभवन में गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने सर्वप्रभूत्व संपन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की तो ३२ करोड़ भारतीयों के हृदय आनन्दातिरेक से परिपूर्ण हो गये। तब उन्होंने यही अनुभव किया कि एक शताब्दी के सतत बलिदान का फल उनके सामने मूर्त रूप में प्रगट हुआ है। उसी समय से यह अनुभव होने लगा कि हम एक नये पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। डा. राजेन्द्र प्रसाद का हिन्दी में राष्ट्रपति के पद की शपथ लेना और दरबार हाल में अपना प्रथम भाषण हिन्दी में देना इस बात के सूचक थे कि अब जन-वाणी को उसके उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। राजेन्द्र बाबू के ये शब्द बड़े उद्बोधक थे :- ''इस देश में आज से न कोई राजा रहा और न कोई प्रजा। या तो सब के सब राजा हैं या सब प्रजा। इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब सारा देश काश्मीर से कन्या कुमारी तक और काठियावाड़ और कच्छ से कोकोनाड़ा और कामरूप तक एक से विधान के शासनसूत्र में बंधकर ३२ करोड़ मनुष्यों के सुख-दुख की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहा है।'' इन शब्दों के साथ प्रत्येक भारतीय ने अनुभव किया होगा कि देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति तभी संभव है जबकि यह भी अपना योग दे।

गणराज्य दिवस पर केवल राजधानी में ही चहल-पहल नहीं रही, बल्कि देश भर में तथा विदेशों में भी यह बड़े उत्साह व उल्लास के साथ मनाया गया। कुछ लोग, जो जिम्मेदारी का कुछ खयाल न कर भोले-बेगौके सरकार को खरी-खोटी सुनाते रहते हैं और यह कहते भी नहीं झिझकते कि नव-अर्जित स्वतन्त्रता तथा वर्तमान नेताओं के प्रति जनता उदासीन होती जा रही है, इस महान समारोह में प्रदर्शित जनता के उत्साह को देखकर दंग रह गये होंगे।

फिर संयम से ही संभला श्रद्धा का संगम

प्रमोद तिवारी | पूर्व पुलिस महानिदेशक

प्रयागराज में कुम्भ की रौनक और लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है, पर मौनी अमावस्या पर सुबह होने से पूर्व जो भगदड़ मची, उसकी वजहों को बहुत संवेदना के साथ परखना होगा।

इन दिनों महाकुम्भ नगर में करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, पर बाकी दिनों में इस पूरे क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है। कुम्भ के आयोजन से एकाध वर्ष पहले ही बड़े अधिकारियों को वहां पदस्थ कर दिया जाता है। कुम्भ मेला का गोदाम होता है, जहां मेले की पुरानी सारी जरूरी चीजें रखी रहती हैं। इनमें अभिलेख भी रखे होते हैं। उन सबका अध्ययन करके तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जाता है। एक कुम्भनगर की पुनर्रचना होती है। होता यह है कि हर बार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। सूचना और संचार के साधन बढ़े हैं, पर मेला क्षेत्र की भी एक सीमा है, उसे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। इस बार भी भीड़ का अनुमान प्रशासन को पहले से था और इसीलिए मेला क्षेत्र का बहुत विस्तार किया गया, पर दुर्भाग्य से एक कसर रह गई।

फिर भी मौनी अमावस्या पर सुबह होने से काफी पहले जो त्रासद भगदड़ मची, उसकी वजहों को बहुत संवेदना के साथ परखना होगा। परंपरा के अनुसार, वर्षों से लोग इच्छा या कामना संजोए रहते हैं कि कुम्भ स्नान करना है और उसमें भी मौनी अमावस्या पर स्नान को लोग कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। स्नान में भी संगम नोज या संगम तट पर स्नान को तीर्थयात्री अत्यधिक महत्व देते हैं। पुरानी धारणा बनी हुई है कि प्रयाग जाएंगे, तो संगम तट पर स्नान करेंगे। लाखों लोग जब संगम पर स्नान के लिए एक साथ लालायित हो जाते हैं, तब सबको संभालना कठिन हो जाता है। बाकी स्नान के दिन तो भीड़ का प्रबंधन हो जाता है, पर मौनी अमावस्या के दिन व्यवस्थाएं कमतर नजर आने लगती हैं। निस्संदेह, मेला प्रशासन के पास भीड़ प्रबंधन के अनेक तरीके होते हैं। लोगों को व्यवस्थित गलियारों में निर्देशित किया जाता है, ताकि भगदड़ न हो और लोग धीरे-धीरे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए स्नान स्थल तक पहुंच जाएं।

बुधवार को जो हादसा हुआ है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझना होगा कि कुम्भ में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कई दिनों तक यहीं ठहर जाते हैं। शिविरों, अखाड़ों में उन्हें जगह भी मिल जाती है और भंडारों की वजह से भोजन की भी चिंता नहीं रहती है। लोगों को बुलाया भी जाता है और सुविधा देख बड़ी संख्या में लोग सपरिवार कुम्भ आ जाते हैं। एक बात यह भी है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से लोगों को लग रहा है कि महाकुम्भ में तमाम व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हैं, तो लोग बड़ी संख्या में प्रयाग पहुंच रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से ही ज्यादा लोग वहां ठहर रहे हैं।

मौनी अमावस्या के दिन स्नान का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त पर स्नान करने के मकसद से बहुत से लोग संगम नोज या संगम तट पर रात के समय ही पहुंच जाते हैं और वहीं रुककर मुहूर्त का इंतजार करते हैं। संगम तट को प्रशासन चूंकि पूरी तरह से खाली रखता है, पर मना करने के बावजूद बहुत से लोग तट या घाट पर खुले में ही बैठ या लेट जाते हैं। संभवतः इन लेटे हुए लोगों को ही भीड़ के एकाध रेले ने बैरिकेट तोड़कर कुचल दिया। अनियंत्रित भीड़ जब आगे बढ़ी, तब खुद को रोक न पाई और इसी वजह से जनहानि हुई है।

हालांकि, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद प्रशासन ने ही नहीं, बल्कि स्वयं साधुओं ने भी बहुत समझदारी और संयम का परिचय दिया। सुबह साधुओं और अखाड़ों ने स्वयं घोषणा कर दी कि वे स्नान के लिए नहीं जाएंगे। पहले बाहर से आए लोग स्नान कर लें, भीड़ संभल जाए, उसके बाद ही अखाड़ों का स्नान होगा। साधुओं ने कुम्भ में फिर बड़ी सदाशयता का परिचय दिया। हादसे को देखते हुए स्नान की होड़ से पीछे हट गए। इस बीच प्रशासन को व्यवस्था सामान्य करने का पूरा समय मिल गया। प्रशासन ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ितों की सेवा और जीवन रक्षा में जुट गया। सरकार कितनी चिंतित थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब चार बार फोन करके जायजा लिया। इससे भी स्थितियों को जल्दी संभालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्था में लगे रहे। तत्परता से प्रशासन ने स्थितियों को संभाला, ताकि लोग किसी भी तरह की अफवाह या दहशत में आने से बच जाएं। प्रशासन ने बाकी लोगों के स्नान को रुकने नहीं दिया। दोपहर बाद अखाड़ों का भी स्नान पूरी सुविधा के साथ शुरू हो गया और लोगों की आवाजाही पर भी असर नहीं पड़ने दिया गया।

बहरहाल, फिर कभी ऐसा हादसा न हो, इसके लिए हमें विचार करना होगा। वैसे इसमें प्रशासन या मानवीय चूक जैसी कोई बात नहीं है। अब समय आ गया है, जब प्रशासन को मेला क्षेत्र का और विस्तार करना होगा, विशेष रूप से स्नान क्षेत्र का विस्तार जरूरी हो गया है। संगम नोज या तट पर दबाव को कम करने की जरूरत है। हमें आने और जाने के रास्ते बढ़ाने पड़ेंगे। हमें समझना और समझाना होगा कि केवल संगम क्षेत्र ही स्नान के लिए पवित्र नहीं है, पूरा मेला क्षेत्र, प्रयाग गंगा, यमुना के तमाम तट पवित्र हैं। मेला क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाता है, तो यहां पूरा क्षेत्र स्नान योग्य है। संगम स्नान को लेकर जो मिथक है, उसे तोड़ने की जरूरत है और इसमें हमारे साधु-संन्यासियों का बहुत अहम योगदान होगा। हादसे के बाद कुछ संतों ने कहा भी है कि पुण्य क्षेत्र में कहीं भी स्नान करलो, पूरा क्षेत्र समान रूप से पवित्र है। अन्य संतों को भी आगे आकर लोगों को समझाना होगा कि देखिए, संगम पर स्नान की एक सीमा है। वहां एक लाख की फौज भी खड़ी हो जाए, तो व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

एक बात यह भी है कि तट पर सोने-लेटने की अनुमति किसी को नहीं हो और प्रशासन ऐसा करने से लोगों को रोकता भी रहता है, पर लोग नहीं मानते हैं। अब खुद लोगों को भी तट पर ज्यादा टिके रहने के जोखिम को समझना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम स्नान के दिनों में तट पर बैठकर या लेटकर न तो बाधा बनेंगे और न अपने जीवन को संकट में डालेंगे। विशाल आबादी वाले अपने देश में ऐसे हादसों से हमें सीखना ही चाहिए और इससे न किसी का हौसला कम हुआ है और न होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आपात स्थितियों से निपटने के लिए बने अलग विभाग

अंजुली भार्गव | नीति-विशेषज्ञ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी बजट बनाते हुए यह तय करने में जुटी होंगी कि कर के पैसे से किसे कितना मिलना चाहिए, मेरा मानना है कि हादसों में जख्मी लोगों को तत्काल और जरूरी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की खातिर ट्रॉमा केयर के लिए एक अलग से विभाग गठित होना चाहिए। बड़ी संख्या में भारतीय रोजाना ट्रॉमा का सामना करते हैं। इसे आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं से जोड़ा जाता है, पर कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिनमें जख्मी लोगों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ उदाहरणों पर नजर डालिए:-

गुजरात के मोरबी में पुल ढहने से 141 लोगों की मौत हो गई थी और 180 लोग घायल हो गए थे, जिनके लिए ट्रॉमा केयर की जरूरत थी। इसी तरह, पिछले पांच वर्षों में देश के 17 रेलवे जोन में 200 रेल हादसे हुए, जिनमें 350 लोगों की मौत हुई और करीब 1,000 लोग घायल हुए। किसी अन्य घटना से ज्यादा तो देश में बलात्कार, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा के पीड़ितों को लगातार व गहन ट्रॉमा केयर की जरूरत पड़ती है। इनमें से कई मामलों में शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक आघात नुकसानदेह होता है, पर अपने देश में इससे निपटने की व्यवस्था कमोबेश नदारद है। साल 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि सड़क हादसों में ही लगभग दो लाख लोगों की जान गई, जिनमें से करीब 45 फीसदी मामलों में चिकित्सकीय सहायता न मिल पाने के कारण मौत हुई।

सामान्य चिकित्सा की तुलना में ट्रॉमा केयर अधिक संवेदनशील मसला है और अब तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा है।

भारत में दूसरे व तीसरे स्तर के शहरों में आपातकालीन और आपात देखभाल संबंधी विषय पर नीति आयोग का एक हालिया अध्ययन बताता है कि यहां भले ही 91 फीसदी अस्पतालों में अपनी एंबुलेंस की व्यवस्था पाई गई, पर सिर्फ 34 फीसदी में प्रशिक्षित नर्स या सहायक थे और कई अस्पतालों में एंबुलेंस पहुंचने से पूर्व आगमन की सूचना देने वाली व्यवस्था का अभाव था। नवंबर, 2024 में 'सेवलाइफ फाउंडेशन' ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर कर केंद्र व राज्य सरकारों से आपातकालीन आघात अधिकार की गारंटी देने की मांग की थी। दिक्कत यह है कि भारत में अस्पतालों, क्लिनिकों व स्वास्थ्य केंद्रों को देखभाल की उनकी सुविधा के स्तर की बुनियाद पर नहीं बांटा गया है। इसके कारण, एंबुलेंस दुर्घटना पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाती हैं, बजाय इसके कि जहां उन्हें जरूरी सुविधा मिल सके। सितंबर, 2022 में टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हादसे के बाद ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां दिमागी चोट के इलाज की व्यवस्था नहीं थी।

हादसों में जान बचाने के लिए जरूरी यह भी है कि दुर्घटना स्थल पर नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाए। कई देशों के स्कूलों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इसी तरह, एक सार्वभौमिक नंबर का भी अभाव है, ताकि पुलिस, अग्निशमन और एंबुलेंस जैसी सभी आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर से मिल सकें। हालांकि, एक नंबर 112 है, जिसके तहत ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है और केरल को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में यह उपलब्ध भी है, लेकिन इसके बारे में सबको पता नहीं है और यह सभी राज्यों में आपात सेवाओं को एक भी नहीं करता है। इसी तरह, एंबुलेंस में प्रशिक्षित चिकित्सकर्मियों का होना सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि राज्यवार एंबुलेंस की गुणवत्ता में भारी अंतर है। अपेक्षा यह भी है कि जख्म की प्रकृति के अनुसार एंबुलेंस को अस्पतालों तक भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए और अस्पतालों को पहले ही इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मरीज को किस इलाज की जरूरत है। सड़कों के किनारे दुकान आदि लगाने वालों में यदि कोई प्राथमिक इलाज देने में सक्षम है, तो उसे भी इसका बुनियादी प्रशिक्षण देना चाहिए।

सवाल उठ सकता है कि इसके लिए अलग से मंत्रालय क्यों? दरअसल, सामान्य चिकित्सा देखभाल की तुलना में ट्रॉमा केयर कहीं अधिक संवेदनशील मसला है और अब तक किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा है। जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने समाज में बनती दूरियों से निपटने के लिए नए मंत्रालयों की स्थापना की है। हमें भी अपनी जरूरतों के मद्देनजर ट्रॉमा केयर मंत्रालय का गठन करना चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आध्यात्मिक ज्ञान का आधार

कभी आपने इस सवाल पर चिंतन-मनन किया है कि सत्य का ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है, बाहरी विषयों को आत्मसात करना। यह व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, यानी धन, सुख, पद और भौतिक वस्तुओं से विरक्त होकर व्यक्ति आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, तो उसका ध्यान शरीर व भौतिक दुनिया से हटकर आत्मा और चेतना की ओर चला जाता है। जहां ऐसी मानसिकता पाई जाती है, वहां ज्ञान है और जहां यह नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है।

जहां ज्ञान भौतिक है, वहां उसका आधार मन होता है और जहां ज्ञान पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वहां उसका आधार आत्मा है। ज्ञान मन को आत्मा के साथ जोड़ता है, और यही उसकी प्रमुख विशेषता है। जो मन को आत्मा से नहीं जोड़ता, वह ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी भ्रांति है। इस कारण ज्ञान से अगर मन में अहंकार पैदा होता है, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं।

युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजकुमार थे। उन्होंने युद्ध-परिणाम को लेकर कौरवों को समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान से भी प्रार्थना की कि वह कौरवों को धर्म और सत्य का रास्ता दिखाएं, ताकि वे समझ सकें कि युद्ध विनाशकारी होगा। कौरवों का मन भौतिक और अहंकारी था। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर की बातों को नकार दिया। वहीं, जब अर्जुन युद्ध से संकोच कर रहे थे और उनके मन में बवंडर मच गया था, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें *गीता* का उपदेश दिया।

व्यक्ति अपने निर्णयों में केवल बाहरी परिणामों और भौतिक लाभ-हानि के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसका मन आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक होता है, तो वह गहरे सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग को समझता है। सांसारिक ज्ञान पहले भौतिक स्तर पर होता है, बाद में यह मानसिक स्तर पर विकसित होता है। ऐसे ज्ञान का सीमित मूल्य होता है, और यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें आज जो सिद्धांत पसंद किया जाता है, वह कल बदल सकता है।

यथार्थ ज्ञान उस सत्ता का ज्ञान है, जिसमें समय, स्थान और व्यक्ति के बदलाव से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस संसार में हरेक वस्तु और घटना का एक कारण होता है और वही कारण परिणाम बनता है। जहां कार्य-कारण का सिद्धांत लागू होता है, वहां अपूर्णता रहती है। इस ज्ञान का कोई अहंकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक-मानसिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है, तो उसके ज्ञान का स्रोत आंतरिक आध्यात्मिकता होती है। यह वह ज्ञान है, जो मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है, क्योंकि इसका अंत आध्यात्मिक ज्ञान में होता है। यही एकमात्र सत्य ज्ञान है!

जहां ज्ञान भौतिक है, वहां उसका आधार मन होता है और जहां ज्ञान पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वहां उसका आधार आत्मा है। ज्ञान मन को आत्मा के साथ जोड़ता है और यही उसकी विशेषता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

भारतीय गणतंत्र की गौरवशाली यात्रा के दौरान देश के आर्थिक विकास और उत्थान में व्यापारी समुदाय ने महती भूमिका निभाई है। मेरी अपील है कि विकसित भारत के निर्माण में हमारे व्यापारी पूर्ण सामर्थ्य और समर्पण से जुटे रहें।

गांधी व्यक्ति नहीं, एक चेतना का नाम

वह कुछ नहीं थे, उनको कोई तमगा भी नहीं मिला। उनके नाम के आगे 'श्री श्री' भी नहीं लगता, फिर भी करोड़ों भारतीय उन्हें 'साबरमती का संत' कहकर आदर देते हैं। चर्चिल उन्हें अधनंगा फकीर कहते थे, मगर अंग्रेज उनसे डरते थे। वाकई महात्मा गांधी महान थे। आज (30 जनवरी) उनकी पुण्यतिथि है। यह विडंबना ही है कि बीते कुछ वर्षों में उन्हें कमतर दर्शाने की एक साजिश चल रही है, जबकि उन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती 40 साल इस देश की आजादी के लिए खर्च किए। इसीलिए, जब कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनकी प्रासंगिकता अब नहीं रही, तो उनकी नादानी पर हंसी ही आती है।

टैगोर का वह महात्मा, जो अपने आखिरी दिनों में इस दुनिया में व्याप्त हिंसा से निराश, बदहवास और अकेला था, मौत के बाद पूरी दुनिया का महात्मा हो गया। जब देश में लोग आजादी और नई सत्ता का स्वागत कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने खुद को अकेला कर लिया और नोआखली से दिल्ली तक भाग-भागकर मनुष्यता को बचा लिया। गांधी में वह शक्ति थी कि जब वह गाते 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम...', तो उनके पीछे क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी गाने लगते थे। न हिंदू कहता कि मेरा राम श्रेष्ठ है, न मुसलमान कहता कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। तब एक ऐसा मंजर उभरता, जैसे सारी मानवता एक हो। आजाद भारत ने गांधीजी से प्रेरणा ली और धर्म को राष्ट्र-राज्य की खुनियाद नहीं बनाया।

जिस गांधी ने अंग्रेजों से लड़कर इस देश की आजादी जीती थी, उसी देश में गांधी स्वतंत्र भारत की सरकार से अपनी चेतना की आजादी नहीं जीत पाएं। इस देश में उनकी लाठी तोड़ दी जाती है, तो कभी चश्मे और कभी उनकी मूर्तियां। गांधीजी की हत्या पर मिठाइयां बांटने वाले लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहां महात्मा गांधी उन्हें पहले से मौजूद मिलेंगे। जो गांधीजी के मूल्यों पर, उनके महान व्यक्तित्व पर हमला करते रहते हैं, वे एक दिन फिर से हारेंगे। महात्मा गांधी को मिटाने का प्रयास करने वाले नहीं जानते कि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना का नाम है। हम उनसे हर दिन सीखते हैं। वह हमारे प्यारे बापू हैं, हमारे भारत के विश्व पुरुष हैं। गांधी मानवता का नाम है। दुनिया के लिए दुख उठाने का नाम है। त्याग का नाम है। प्रेम का नाम है। भारत की एकता और अखंडता का नाम है। मानव जीवन के मूल्यों का नाम है। कुल मिलाकर, यही कहना उचित होगा कि इस दुनिया में मानवता जब तक जिंदा रहेगी, महात्मा गांधी का नाम लेने वाले जिंदा रहेंगे।

जयप्रकाश नवीन, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
बलिदान दिवस

शांति नहीं, अब आक्रामकता की जरूरत

गांधी अगर प्रासंगिक होते, तो ये खूंखार पड़ोसी होते ही नहीं। भारत का विभाजन होता ही नहीं। महात्मा गांधी राजनेता के तौर विफल रहे। हां, वह एक कुशल संगठनकर्ता जरूर थे और उनका स्वराज का सिद्धांत व गांवों को स्वावलंबी उद्योग से आत्मनिर्भर बनाने का विचार बहुत अच्छा था। देखा जाए, तो अहिंसा के सिद्धांतों के साथ हम कभी अपने आक्रांताओं से नहीं निपट सकते। हमारे पड़ोसी सभ्यता, विचार और संस्कृति, सब में हमसे भिन्न हैं। उनका आक्रमण सिर्फ सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं है, सभ्यताओं के विस्तार के लिए भी है। ऐसे में, हमें गांधी की नहीं, बल्कि आंधी की जरूरत होगी। ऐसी आंधी, जो हमारे विरोधियों को उड़ा ले जाए। जहां युद्ध अवश्यंभावी हो, वहां पर बुद्ध हमेशा अप्रासंगिक ही रहेंगे।

अनुज अग्रवाल, टिप्पणीकार

गांधीवाद का नुकसान

यह ठीक है कि छोटी-छोटी रियासतों में बंटे इस देश के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध अलख जगाने और भारतीयों को एकजुट करने में मोहनदास करमचंद गांधी की बड़ी भूमिका रही है। उनके इस प्रयास की भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों, मजहबों को एक साथ रखने की कोशिश की। मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश में कोई आंदोलन या क्रांति नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा हो। सच यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की लगातार खराब होती आर्थिक स्थिति के मद्देनजर उसने लगभग सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया था। भारत भी उनमें से एक था। शायद इसीलिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं- भारत की आजादी में गांधी का योगदान नगण्य था। बहरहाल, इस देश ने 'गांधीवाद' की भारी कीमत चुकाई है। सन् 1948 के कश्मीर युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही थी, तब गांधीवाद रूपी रोग से पीड़ित पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए। यह संभवतः विश्व इतिहास में पहला और अनूठा मामला था, जब जीतने वाली सेना न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र में गई हो। उनके उस कृत्य का नासूर हम आज भी भुगत रहे हैं। 1962 की जंग भी हम इसी सफलता में हारे कि गांधीवाद से ही देश और विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसे उदाहरण कई हैं, लेकिन लब्बोलुबाब यही है कि गांधीवाद सज्जनों के सामने ही कारगर होता है, दुर्जन इसे कायरता समझते हैं। उनके साथ 'शठे शाठ्यम समाचरेत' का सिद्धांत ही लागू करना पड़ता है।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 296

शिक्षा के स्तर के नतीजे से सबक

गैर-सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) आमतौर पर एक गंभीर रिपोर्ट मानी जाती है जो भारत के स्कूलों में सीखने के अंतर का जायजा लेती है। उम्मीद के मुताबिक महामारी के दौरान लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से स्थिति और भी खराब हो गई। हालांकि, मंगलवार को जारी नई रिपोर्ट के नतीजे कई मायने में उत्साहजनक हैं। इसके मुताबिक भले ही स्कूलों में सीखने में व्यापक अंतर मौजूद है लेकिन इस सर्वेक्षण के अनुसार कई सकारात्मक निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है और देश को अब इस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है।

पहला, ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक महामारी के दौरान सीखने के स्तर में जो कमी देखी गई थी अब वह दुरुस्त हो गई है। दूसरा, प्री-प्राइमरी के स्तर पर महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है। तीसरा, अब 14-16 वर्ष की उम्र के बच्चों में डिजिटल जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। असर 2024, एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण परिवारों पर आधारित एक सर्वेक्षण है जिसके तहत देश के 605 जिले के 350,000 घरों और करीब 650,000 बच्चों से संपर्क किया गया। इस सर्वेक्षण में करीब 18,000 गांव और 15,000 से अधिक स्कूल शामिल थे। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अनिवार्य रूप से 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के तय नामांकन लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया गया है। इस उम्र वर्ग के लगभग 1.9 प्रतिशत बच्चे स्कूल में नहीं हैं जो 2022 के 1.6 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। हालांकि, रुझान दर्शाते हैं कि आरटीई के तहत बच्चों के जिस उम्र समूह को शामिल नहीं किया जाता है उनमें भी स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का अनुपात समय के साथ घट रहा है। जहां तक सीखने से जुड़े नतीजों की बात है, उस लिहाज से न केवल महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हुई है बल्कि कुछ मामलों में नतीजे पहले की तुलना में बेहतर हैं। उदाहरण के तौर पर, कक्षा 5 के बच्चों का अनुपात जो बेहद बुनियादी भाग (तीन अंकों को एक अंक से भाग देना) करना जानते हैं उनकी तादाद 2018 में 27.9 प्रतिशत थी जो 2022 में घटकर 25.6 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि 2024 में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गई जो 2014 में ऐसे बच्चों की 26.1 प्रतिशत की तादाद से बहुत अधिक है। इसी तरह के रुझान अन्य पहलुओं में भी देखने को मिले और यह सुधार सरकारी स्कूलों की बदौलत देखा गया।

रिपोर्ट में एनईपी की भूमिका और इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ गणना से जुड़े पहलुओं पर जोर देने के कारण बेहतर परिणाम दिखने की बात का जिक्र है। पिछली योजनाओं से उलट राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे नतीजे दिख रहे हैं। अधिकांश स्कूलों को इस संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। प्री-प्राइमरी स्तर पर भी नामांकन में अहम बदलाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पर, तीन साल के बच्चों में, नामांकन का स्तर 2018 में 68.1 प्रतिशत था जो 2024 में बढ़कर 77.4 प्रतिशत हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र इस उम्र वर्ग के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। यह एक स्वागत योग्य रुझान है। नामांकन बढ़ने से बच्चे न केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार होंगे बल्कि इससे टीकाकरण और इससे जुड़े सभी पहलुओं की दिशा में काम करते हुए उनके समग्र विकास में योगदान दिया जा सकेगा।

इसके अलावा, असर ने पहली बार अपने सर्वेक्षण में 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच डिजिटल साक्षरता के बिंदु को शामिल किया। लगभग 90 प्रतिशत बच्चों ने घर पर स्मार्टफोन होने और 80 प्रतिशत से अधिक ने इसका इस्तेमाल करने की जानकारी दी। इस उम्र के बच्चों में खुद को ऑनलाइन रखते हुए सुरक्षित रखने के बुनियादी तरीकों से जुड़ी जागरूकता भी अपेक्षाकृत अधिक थी।

स्मार्टफोन की बड़े स्तर पर उपलब्धता से शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल के अवसर भी मिलते हैं। व्यापक तौर पर नए सर्वेक्षण में कई सकारात्मक बातें हैं लेकिन इसके बावजूद नीति निर्माताओं और बाकी हितधारकों को अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के डेटा कुछ मौजूदा अंतर के स्तर को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुधार के बावजूद, कक्षा 5 के 50 फीसदी से अधिक बच्चे, कक्षा 2 के स्तर के पाठ को नहीं पढ़ सकते थे। मौजूदा आर्थिक माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता है क्योंकि भारत की दीर्घकालिक समृद्धि और बेहतरी इस पर ही निर्भर है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्राथमिकताएं

वित्त मंत्री की भूमिका जिन कार्यक्रमों में सहायक जैसी हो, बजट में उन पर ध्यान देने के बजाय सीतारमण को अपनी सीधी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी हफ्ते 2025-26 का बजट पेश करेंगी। पुराने रुझान देखें तो उनके भाषण का बड़ा हिस्सा विकास कार्यक्रमों और अन्य मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में होगा। गत वर्ष वित्त मंत्री के बजट भाषण में 165 पैराग्राफ शामिल थे और इनमें से ज्यादातर में व्यय प्रस्तावों की ही बात थी। बजट का तकरीबन 79 फीसदी हिस्सा इसी पर केंद्रित था। व्यय प्रस्तावों में प्राथमिक तौर पर कार्यक्रमों की बात थी, जो यकीनन उन सरकारी विभागों ने तैयार किए होंगे, जिनके जिम्मे उनका क्रियान्वयन होता है।

वित्त मंत्री को व्यय के तरीके का इशारा देने किए विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों के वास्ते धन की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बजाय उन्हें वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के नजरिये से इसे देखना और दिखाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान बजट भाषणों में तमाम सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे विकास के प्रयासों का प्रचार-प्रसार को कुछ ज्यादा अहमियत दी गई है।

इसे बदलना होगा। बजट का अधिकांश हिस्सा वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों और उपायों पर केंद्रित होना चाहिए। इन उपायों में बजट प्रबंधन खास है यानी बजट के संसाधन किस तरह जुटाए जाएंगे और वृद्धि तथा विकास पर इनका क्या प्रभाव होगा। इसमें खरीदारों और विक्रेताओं तथा बचतकर्ताओं और निवेशकों को मिलाने वाली वित्तीय मध्यवर्ती व्यवस्था तैयार करने और संभालने की रणनीति भी शामिल होनी चाहिए। इसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि पिछले साल के बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं के क्या नतीजे निकले।

वित्त मंत्रालय का सबसे अहम प्रभाव अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक और मध्यम अवधि की तात्कालिक संभावनाओं पर पड़ता है। फिलहाल वृद्धि के मामले में सबसे अहम नीतिगत चुनौती है विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और दीर्घकालिक संभावनाओं में धीमापन। कोविड वाले साल छोड़ दिए जाएं तो तयशुदा निवेश में तेजी से उछाल आई और 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार यह वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 31.3 फीसदी हो गया। अब भी यह 2011-12 के 34.3 फीसदी के उच्चतम स्तर से कम है। राष्ट्रीय लेखा से यह भी पता चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण और खनन में तयशुदा निवेश की हिस्सेदारी 2022-23 में 5.3 फीसदी रह गई, जो 1990-91 में उदारीकरण शुरू होने पर 6.4 फीसदी थी। सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी 1990-91 के 21 फीसदी से कम होकर 2022-23 तक 16 फीसदी रह गया।

सेवा क्षेत्र में भारी इजाफा हुआ और जीडीपी के अनुपात के रूप में तयशुदा निवेश की हिस्सेदारी 1990-81 के 4.5 फीसदी से बढ़कर 2022-23 तक 9.2 फीसदी हो गई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उदारीकरण के बाद वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सेवा उपक्रमों में इजाफे के रूप में सामने आया खास तौर पर निर्यात करने वाली आईटी कंपनियों और ई-कॉमर्स तथा ई-फाइनैंस में तेज वृद्धि के रूप में।

बजट निर्माण में एक अन्य अहम कारक है 1991 के उदारीकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र पर जोर देना। मगर निवेश में इस बदलाव से कंपनियों की खर्च करने की क्षमता इतनी नहीं बढ़ पाई कि वह राजकोषीय प्रणाली के जरिये निवेश संसाधन जुटाने की सार्वजनिक क्षेत्र की उस क्षमता का मुकाबला कर सके, जो उदारीकरण से पहले थी। साथ ही बजट संसाधन भी तयशुदा निवेश से हटाकर सब्सिडी और मुफ्त उपहारों में खर्च किए जाने लगे हैं। इसके कारण केंद्र सरकार की देनदारियों के अनुपात में उसकी संपत्तियां काफी कम हो गईं। 1950-51 में यह अनुपात 67 फीसदी था, जहां से बढ़कर 1960 के दशक के आरंभ में 100 फीसदी हो गया और 1980 के आरंभ तक इसी स्तर पर बना रहा क्योंकि सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और बुनियादी ढांचा निकायों में निवेश पर जोर दिया गया। तब से अब तक इसमें लगातार गिरावट आई है और 1990-91 के 75 फीसदी से कम होकर यह 2023-24 तक 42 फीसदी रह गया। इस दौरान सब्सिडी और मुफ्त रेवड़ियों पर ज्यादा जोर दिया गया। चुनावों में रेवड़ियों की बढ़ती भूमिका ने भी सरकार का परिसंपत्ति-देनदारी अनुपात कम किया होगा।

सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया था और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया था लेकिन इसका कारोबारी निवेश पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। वित्त मंत्रालय को समझना होगा कि कंपनियों से निवेश को बढ़ावा मांग बढ़ने और प्रतिस्पर्द्धा की संभावना होने से मिलता है। इन दोनों को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली कई नीतिगत पहलों की मदद से गति दी जा सकती है। इस वर्ष बजट भाषण में प्राथमिक रूप से ध्यान यह बात की जानी चाहिए कि उसकी नीतियां मांग में वृद्धि को गति देने के लिए क्या करेंगी और देश के भीतर तथा बाहर होड़ पर उनका क्या असर होगा। आय वितरण पर कर ढांचे के असर की बात करें तो हालिया वर्षों में उसे शायद ही भी इतना अधिक महत्त्व मिला हो। मांग में वृद्धि पर इसके असर को ही ज्यादा तरजीह दी गई है। देश के भीतर मांग बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो वह व्यक्तिगत कर की दरों निर्धार करेगा, जो फिलहाल ठीक हैं और उनमें फेरबदल महंगाई के हिसाब से ही की जानी चाहिए। हाल ही में बिना किसी बड़ी रियायत के वैकल्पिक दरों में किए गए बदलाव प्रभावी नजर आते हैं। व्यक्तिगत आयकर में बदलाव वेतनभोगी मध्य वर्ग और छोटे उद्यमियों की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ेगा।

किंतु हमें मांग में जिस वृद्धि की जरूरत है वह निम्न आय समूहों से आती है, जो कर दायरे से बाहर हैं। इस पर असर का आकलन करने के लिए देखना होगा कि बजट के कार्यक्रम और नीतियां छोटे उद्यमों की वृद्धि को कितनी रफ्तार देती हैं क्योंकि भारत में कृषि से हटकर रोजगार बढ़ाने का यह अहम जरिया है। वित्त मंत्री ने गत वर्ष के बजट में सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को लेकर कुछ सहायक कदमों की घोषणा अवश्य की थी। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस दिशा में गत वर्ष क्या हासिल हुआ खास तौर पर उत्तर के राज्यों में। यह वित्त मंत्रालय की सीधी जवाबदेही वाला ऐसा क्षेत्र है, जो गरीबी और असमानता में कमी लाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

जहां तक बात कॉरपोरेट क्षेत्र की महत्त्वाकांक्षा को बढ़ावा देने की है तो इसकी कुंजी उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा प्रक्रिया विकास में निहित है। इसका सबसे प्रभावी उपाय है देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक होड़ के लिए खोलना। इसके लिए शुल्कों के जरिये देसी उद्योगों को सुरक्षा देने का रवैया छोड़ना पड़ेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उदार नीति अपनानी होगी। गत वर्ष के बजट में निजी क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कार्यक्रम शामिल था। वित्त मंत्री को बताना चाहिए गत वर्ष इसका किस प्रकार क्रियान्वयन किया गया।

वित्त मंत्रालय के लिए एक और अहम काम है वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र के बल पर वृद्धि हासिल करने के लिए यह जरूरी है। हाल के वर्षों में कई सकारात्मक घटनाएं घटी हैं, इनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, इंटरनेट पर काम करने वाले वित्तीय मध्यस्थों तथा यूपीआई का तेज विस्तार शामिल है, जिससे एमएसएमई के लिए मार्केटिंग के नए अवसर तैयार होते हैं। एक क्षेत्र जिसमें पहल करने की जरूरत है वह है देसी वेंचर कैपिटल फाइनैंसिंग को बढ़ावा देना। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टअप रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। वित्त मंत्री को अपने भाषण का बड़ा हिस्सा वित्तीय मध्यस्थों के विकास की व्यापक रणनीति बताने में लगाना चाहिए।

मोटे तौर पर कहें तो तो वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में उन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिनके लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं न कि उन कार्यक्रमों पर जहां उनकी भूमिका सहायक की ही रही है।

बजट में दिख पाएगा कुछ अलग करने का साहस?

साल का यह बहुत अहम समय है। फरवरी की पहली तारीख को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा और उसके हफ्ते भर के भीतर 7 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत बैठक शुरू हो जाएगी। नीति निर्माताओं के सामने बेहद पेचीदा स्थिति आ गई है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को फिर शुरू करना, उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना और राजकोषीय घाटे के बारे में तय रास्ते पर आगे बढ़ना कोई आसान बात नहीं है। आसान बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एकदम धीमी है, कर राजस्व में भी सुस्त रफ्तार से इजाफा हो रहा है तथा विदेश में तस्वीर अनिश्चितता भरी है।

सबसे पहले दुनिया पर नजर डालते हैं। फेडरल रिजर्व ने 2025 में दर कटौती की तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड गिर सकती है मगर डॉलर ऊंचा ही बना रहेगा क्योंकि इसे अमेरिका के अपवाद भरे प्रदर्शन से ही नहीं बल्कि वहां बदलती शुल्क नीतियों और अप्रत्याशित भू-राजनीति से भी ताकत मिलती है। इससे उभरते बाजारों की मुद्राओं जैसे रुपये पर दबाव पड़ रहा है और उसमें आगे भी गिरावट बनी रह सकती है।

देश की बात करें तो वृद्धि दर 6.5 फीसदी से भी नीचे जा चुकी है। नीतिगत बढ़ावे से यह बढ़कर 6.5 फीसदी तक पहुंच सकती है। मगर बढ़ावा देने लिए उपाय क्या हो - खजाने से ज्यादा सहारा दिया जाए या मौद्रिक नीति में नरमी बरती जाए?

सबसे पहले राजकोषीय स्थिति समझते हैं। अच्छी खबर है कि सरकार राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष के अपने लक्ष्य से भी नीचे ला सकती है। बजट में इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी पर रोकने का लक्ष्य था मगर यह और घटकर 4.8 फीसदी रह सकता है। ऐसा बजट अनुमान से कम सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के कारण हो रहा है। चुनावी साल में आसानी से मंजूरी नहीं मिलने के कारण व्यय धीमा रहा है।

किंतु वित्त वर्ष 2026 मुश्किल हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार गिरने से पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि लड़खड़ा सकती है। लेकिन चुनाव निपट जाने के कारण पूंजीगत व्यय फिर तेजी पकड़ सकता है। यह अच्छा विचार है क्योंकि आम तौर पर केंद्र ही इतना पूंजीगत व्यय कर देता है कि राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय की गुंजाइश ही नहीं बचती। ध्यान रहे कि पूंजीगत व्यय से फौरन रोजगार ही नहीं आता बल्कि मध्यम अवधि में तेजी से वृद्धि करने की क्षमता भी पैदा होती है।

ऐसे में वित्त मंत्रालय के वादे के मुताबिक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से कम तभी किया जा सकता है, जब मौजूदा व्यय में कटौती की जाए। सब्सिडी तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च कम करना मुश्किल हो सकता है असंभव नहीं। जब खर्च को दुरुस्त करना था तब केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च धीमा हो गया था मगर पिछले कुछ साल में इन पर खर्च फिर बढ़ गया है। शायद एक बार फिर खर्च को कसना पड़ेगा।

प्रांजुल भंडारी

बजट के गुणा-भाग में उम्मीद की किरण भी है। चूंकि हम अच्छी गुणवत्ता वाले पूंजीगत व्यय में तेजी की अपेक्षा कर रहे है, इसलिए खजाने को मजबूती देने के बाद भी अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय प्रोत्साहन पहले जैसा ही रह सकता है। अगर मान लें कि राजकोषीय प्रोत्साहन पहले जैसा ही रहेगा तो असली प्रोत्साहन मौद्रिक नीति से ही आएगा। हकीकत में ऐसा होता दिख रहा है। सब्जियों की फसल अच्छी होने के कारण जनवरी में उपभोक्ता कीमतें केवल 4.2 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, जो अक्टूबर में 6.2 फीसदी बढ़ी थीं। अगर गेहूं की कटाई भी उसकी बोआई की तरह बढ़िया रही तो महंगाई घटने का सिलसिला वित्त वर्ष 2026 में भी जारी रह सकता है। हां, कमजोर रुपया मुद्रास्फीति को चढ़ाएगा मगर अनुमान हैं कि अगले वित्त वर्ष में औसत मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य के आसपास ही रहेगी।

फिर मौद्रिक नीति क्या भूमिकाएं निभा सकती है? हमारे हिसाब से कई भूमिकाएं। हमें लगता है कि दर कटौती में अब ज्यादा देर नहीं है। हमें नहीं लगता कि उसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा क्योंकि इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई अन्य उभरते बाजारों में दरें घटाई गई हैं मगर वहां डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्रा नहीं गिरी। हां, ध्यान रहे कि जोश में दरें एकदम बहुत ज्यादा नहीं घटा देनी हैं।

इसके बाद तरलता की बात आती है। तरलता बढ़ाने के लिए ओएमओ परिचालन, फॉरेक्स स्वैप, लंबी अवधि की वेरिएबल रेट-रीपो और नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में कटौती जैसे कई उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। जरूरी है कि किसी एक उपाय पर बहुत अधिक निर्भर रहने के बजाय सभी उपाय थोड़े-थोड़े इस्तेमाल होते रहें। इनके जरिये अच्छी खासी तरलता बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था को दम मिलेगा।

अंत में सबसे जरूरी पहलू और वह है रुपया। लचीली विनिमय दर और रुपये में कमजोरी कमाल कर सकती है। सबसे पहले तो इससे भारत का निर्यात (विशेषकर सेवा निर्यात) दूसरे देशों के निर्यात से होड़ कर सकता है, जिससे वृद्धि को बल मिलेगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा में कम हस्तक्षेप से देश के भीतर तरलता की तंगी कम हो सकती है। तीसरा, इससे दर और तरलता नीति को मुद्रा बचाने के बजाय वृद्धि बढ़ाने का मौका मिल जाता है। चौथा, इससे उन ऊंचे आयात शुल्कों से होने वाला नुकसान कम या खत्म हो जाएगा, जो दुनिया के अहम देश लगा सकते हैं। पांचवां, निर्यात होड़ करेगा तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिहाज से आकर्षक जगह लग सकता है।

पांचवां पहलू अहम है। भारत को अभी तक अमेरिकी व्यापार तनावों से बहुत फायदा नहीं मिल पाया है मगर दुनिया भर में शुल्कों का डर उसके लिए मौका बन सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के चश्मे से देखें तो भारत को तकनीक के टीकठाक इस्तेमाल वाले वस्त्र और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में अभी तक ज्यादा एफडीआई नहीं मिल पाया है। विदेश से ज्यादा निवेश आएगा तो वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी रोजगार सृजन भी हो जाएगा।

लेकिन भारत को यह मौका लपकने के लिए कई मोर्चों पर मेहनत करनी होगी। उसे विनिमय दर लचीली रखनी होगी, उत्पादन की लागत कम रखने के लिए देसी आयात शुल्कों पर अंकुश रखना होगा, दुनिया भर से एफडीआई का स्वागत करना होगा और मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार करना होगा। अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि इनसे श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले भारतीय निर्यात पर लगे शुल्क कम होंगे।

तो क्या भारत कुछ अलग करने का साहस दिखा सकता है? क्या कमजोर वृद्धि के बाद भी वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर अडिग रह सकता है? खपत को प्रोत्साहन की मांग के बाद भी पूंजीगत खर्च पर जोर दे सकता है? नीतिगत दरों में जल्द कटौती कर सकता है? रुपये की कमजोरी से बेपरवाह रह सकता है? पूरी दुनिया कुछ भी करे क्या वह एकसमान शुल्क लगाने या शुल्क के अलावा दूसरी बाधाएं तैयार करने से परहेज कर सकता है? अंत में, क्या वह चीन जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने तथा एफडीआई हासिल करने के लिए तैयार हो सकता है?

यह जरूरी होगा क्योंकि अगर भारत को वृद्धि और रोजगार में इजाफा चाहिए तो पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा।

(लेखिका एचएसबीसी में भारत तथा इंडोनेशिया की मुख्य अर्थशास्त्री तथा प्रबंध निदेशक (ग्लोबल रिसर्च) हैं)

आपका पक्ष

साइबर सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए सरकार

वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया था कि देश में वर्ष 2023 में यूपीआई धोखाधड़ी के मामले लगभग 85 प्रतिशत बढ़े हैं। साइबर अपराध देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ने दुनिया के लगभग 100 देशों के साइबर क्राइम का आंकड़ा जारी किया जिसमें भारत को साइबर क्राइम के मामले में 10वां स्थान मिला जबकि पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे स्थान चीन रहा। अमेरिका भी साइबर क्राइम से अछूता नहीं है। अमेरिका इस आंकड़े में चौथे स्थान पर है। देश में बढ़ते साइबर अपराध के लिए साइबर क्राइम सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए। किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि साइबर चोरों को संभलने का मौका न मिले। रिजर्व बैंक को भी बैंकों को विशेष हिदायत देनी चाहिए।

वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार साइबर क्राइम मामले में भारत 10वें स्थान पर और रूस पहले स्थान पर रहा

साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार और बैंकों ने कदम उठाए हैं। फिर भी साइबर ठगी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कुछ कंपनियां लोगों को ऑनलाइन पुराने सामान की खरीद-बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही, लेकिन साइबर ठग वहां भी सक्रिय है। साइबर ठग लोगों से उनके बैंक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की जानकारी लेकर ठग रहे हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

लोक कल्याण के नाम पर धन की बरबादी रोकने की जरूरत

महज चुनावी रण में विजय प्राप्त कर सत्ता सुख भोगने के लक्ष्य में मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं का दौर जारी है। कर्ज लेकर घी पीने की मानसिकता को त्याग कर सभी सरकारों को सीमित संसाधनों में ही अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लोकलुभावन योजनाओं के नाम पर धन की बरबादी को रोकना चाहिए। बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा राष्ट्रहित में है।

हितेश ललवानी, खंडवा

जनता भी जिम्मेदार

पिछले कुछ वर्षों से चुनाव के पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां इस कदर बांटी जा रही हैं जैसे बिना बटि वे चुनाव नहीं जीत सकते। सरकार को अपने काम के आधार पर व दूसरे दलों को अपनी नीति के आधार पर वोट मांगना चाहिए, न कि रेवड़ियां बांटकर। मुफ्त की रेवड़ियों के लिए जितने राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, उतनी ही जनता भी जिम्मेदार है क्योंकि वह मुफ्त की ज्यादा रेवड़ियां बांटने वाले को ही वोट देती है।

आशीष सकलेचा, जावरा

राज्यों के खजाने पर बोझ

चुनावी मुफ्त रेवड़ियां लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती हैं। ये राज्य के खजाने पर भारी बोझ डालती हैं और मतदाताओं को आत्मनिर्भरता से दूर करती हैं। यह प्रवृत्ति संसाधनों का अपव्यय करती है, जो विकास को रोकती है। ऐसी घोषणाएं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं और जिम्मेदार राजनीति को धूमिल करती हैं। दीर्घकालिक दृष्टि से ये लोकलुभावन वादे समाज को कमजोर कर रहे हैं। साथ ही स्थायी विकास की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में बुधवार को रायसीना अमेरिका-भारत एआई फेलो और रायसीना भारत-अमेरिका के टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक की।

सम्पादकीय

आगामी केंद्रीय बजट में मिल सकती हैं कई सौगात

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत की आर्थिक विकास दर कुछ कमजोर रही है। प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इसी प्रकार द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2024) में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में मुख्य रूप से देश में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव है और आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भरकम कमी दृष्टिगोचर हुई है। साथ ही, देश में मानसून की स्थिति भी ठीक नहीं रही है। केंद्र सरकार ने हालांकि मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने में सफलता तो अर्जित कर ली है परंतु उच्च स्तर पर बनी रही मुद्रा स्फीति के कारण कुल मिलाकर आम नागरिकों विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है और कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों की श्रेणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रहती है, उस देश की आर्थिक विकास दर ऊंचे स्तर पर बनी रहती है क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दो एवं चार पहिया वाहन, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए फ्लैट्स एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग करता है। इससे आर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है। इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे केंद्रीय बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी।

देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि न केवल आयकर में बल्कि कारपोरेट कर में भी कमी की घोषणा की जानी चाहिए। इनफोसिस के संस्थापक सदस्यों में शामिल मोहनदास पई का कहना है कि 15 लाख से अधिक की आय पर लागू 30 प्रतिशत की आयकर की दर को अब 18 लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। आयकर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में लागू 7.75 लाख रुपये की राशि से बढ़ाकर 10 लाख कर देना चाहिए। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत किए जाने निवेश की सीमा को भी 1.50 लाख रुपये की राशि से बढ़ाकर 2 लाख कर देना चाहिए। मकान निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रदान की जाने वाली आयकर छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाना चाहिए। फरवरी महीने में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पोलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। रिजर्व बैंक से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे रेपो दर में कम से कम 25 अथवा 50 आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि, पिछले लगातार लगभग 24 माह तक रेपो दर में कोई भी परिवर्तन नहीं करने के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं चार पहिया वाहन आदि खरीदने हेतु बैंकों से लिए गए ऋण की किस्त की राशि का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। बैंकों से लिए गए इस प्रकार के ऋणों एवं माइक्रो फाइनेंस की किस्तों की अदायगी में चूक की घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुद्रा स्फीति की दर खाद्य पदार्थों के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर पर आ जाती है जबकि कोर मुद्रा स्फीति की दर तो अब नियंत्रण में आ चुकी है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की गणना के अनुसार आज कई विशेष स्थानों पर सूर्य रहेगेगे। यह आज एक सकारात्मक संकेत है कि आपके भीतर के ऐसे गुणों को बल दे, जो आपको जिंदगी सुधार सकेंगे और दुनिया देखा, आपको विशेष बातों में सावधान रहना चाहिए। यह न किसी संकट संकट में और अतिरिक्त खुशी की गुणवत्ता देता सकारात्मक ऊर्जा को समझने वालों, सीमित परामर्शित लक्षणों में भी, जहां यह सकारात्मकता सही संकेत और कारणों में लाभ प्रदान करेगा

मेष
अधिकारियों का रवैया नकारात्मक रहेगा। विरोधियों के साथ वाद-विवाद न करें। संतान से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा की संभावना है। धनखर्च होगा। कार्य सफलता में विलंब होने के कारण निराशा का अनुभव होगा।

वृष
प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे। पत्नी के संग से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा।

मिथुन
काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नए काम की शुरुआत न करें। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा। वाणी पर संयम रखें। खर्च ज्यादा होगा। आज आपका दिन शुभ है। व्यापार बढ़ाने को लेकर आपके प्रयास रंग लाएंगे।

कर्क
आज आप में आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। पिता और बड़ों से लाभ होगा। सामाजिक रूप से मान-सम्मान में वृद्धि होगी। वाणी और व्यवहार उग्रता न हो, इसका ध्यान रखें।

सिंह
मानसिक व्यग्रता को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता, योग का सहारा लें। महिला और पानी से बचकर रहें। अभ्यास के लिए समय मध्यम है। आज आप को ज्यादा संवेदनशील एवं भावुकता भरे विचार आएंगे।

कन्या
आज आप के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आप पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। परिवार में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहेगा। मन में भावनात्मकता बढ़ेगी। मां की ओर से फायदा होगा।

तुला
दूसरों की ओर से चिंता कम होगी। इस कारण आप का मन खुश रहेगा। परिजनों या दोस्तों के साथ अच्छे भोजन का अवसर मिलेगा। कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों से संबंधित व्यवस्था कर सकेंगे।

वृश्चिक
जमीन-जायदाद के दस्तावेजी काम कर सकेंगे। आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं एवं अनुकूलताओं से भरा होगा। लेखन-साहित्य से जुड़े काम कर सकेंगे। हालांकि, व्यवसायिक स्थल पर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी।

धनु
आज रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ मुलाकात से आप आनंद का अनुभव करेंगे। आर्थिक योजना में आपको पहले थोड़ी मुसीबत हो सकती है, आपके जरूरी काम भी शुरुआती विलंब के बाद आसानी से पूरे होने पर शांति का अहसास करेंगे।

मकर
मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे। महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा। अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिलेगी।

कुंभ
महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान रखें। वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें। विदेश से कोई समाचार मिल सकता है। कानूनी बातों का निर्णय सोच-समझकर करें। आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आको लाभ होगा।

मीन
अनुकूल वातावरण रहेगा और साथियों का सहयोग मिलेगा। आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे। दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे। कमिशन, ब्याज से आपकी आय में वृद्धि होगी।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

30 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- डेनमार्क और ल्यूबेक के बीच 1522 में युद्ध।
- पुर्तगाल ने मलक्का की खाड़ी को 1641 में मलाया डचों को सौंप दी।
- हॉलैंड और स्पेन के बीच 1648 में शांति समझौता हुआ।
- इंग्लैंड के सम्राट 'चार्ल्स प्रथम' को 1649 में फांसी दी गई।
- ब्रिटेन के राजकुमार' चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट' की 1788 में रोम में मौत हो गयी।
- लाइफबोट के तौर पर निर्मित पहली नाव का 1790 में टायन नदी में परीक्षण।
- कोरिया और चीन की स्वतंत्रता के बारे में 1902 में जापान और ब्रिटेन के बीच पहली 'आंग्ल-जापानी संधि' पर लंदन में हस्ताक्षर हुए।
- लॉर्ड कर्जन ने 1903 में मेटकाफ़ हॉल में 'इंपीरियल लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया।
- 'कैनेडियन नेवल सर्विस' का नाम 1911 में बदलकर 'रॉयल कैनेडियन नेवी' किया गया।
- 'हाउस आफ लॉर्ड्स' ने 1913 में आइरिश होम रूल बिल को खारिज किया।
- एडॉल्फ हिटलर ने 1933 में आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान सम्भाली।
- सोवियत संघ की एक पनडुब्बी में 30 जनवरी, 1941 को जर्मनी का एक पोत डूब गया, जिससे उसमें सवार करीब 9 हजार लोगों की जान चली गई।
- स्टालिन ग्राफ के पास सोवियत फौजों से 1943 में जर्मन सेना हारी।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन हत्या की थी।
- रात्रि एयर मेल सेवा की शुरूआत 1949 में हुई।
- दक्षिण वियतनाम में सेना ने 1964 में सत्ता पर कब्जा किया।
- दूसरे विश्व युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को 30 जनवरी 1965 को ब्रिटेन के लोगों ने अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि विंस्टन चर्चिल एक प्रखर वक्ता ही नहीं बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।
- इंडियन एयरलाइंस के 'फोकर फ्रेंडशिप विमान' का 1971 में अपहरण।
- पाकिस्तान ने 1972 में 'राष्ट्रमंडल' से अपना नाम वापस लिया।
- अमेरिका ने 30 जनवरी, 1989 को अफगानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया।
- इराकी सेना ने 30 जनवरी 1991 को सउदी अरब की सीमा के पास एक शहर पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण में करीब 12 अमेरिका सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।
- सैंतालिस वर्षों बाद 1997 में महात्मा गांधी की अस्थियाँ संगम में विसर्जित।
- वैज्ञानिकों ने 30 जनवरी साल 2004 को मंगल यान पर भेजे गए अंतरिक्ष यान अपोर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी का एलान किया था।

विशेष आलेख

गांधी निर्वाण दिवस पर विशेष

अब बनने लगा है गांधी के सपनों का भारत

ललित गर्ग

महात्मा गांधी के विचार एवं दर्शन पर ही मोदी सरकार की योजनाएं एवं नीतियां आगे बढ़ रही है। इस बात का खुलासा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए कहा है कि उनके सबका साथ, सबका विकास के विचार की प्रेरणा 1980 के दशक की है। मोदी ने अपने हाथ से लिखे एक नोट्स में इस विचार के बारे में काफी पहले ही लिख दिया था। मोदी द्वारा लिखे गए नोट्स से पता चलता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिसमें युवा मोदी ने महात्मा गांधी के विचारों उद्धरत करके लिखा था, मैं सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी भलाई के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। यह 51 प्रतिशत की अच्छाई के लिए 49 प्रतिशत की भलाई का त्याग करना है। यह सिद्धांत एक क्रूर सिद्धांत है। इसके माध्यम से मानवता को काफी नुकसान हुआ है।

राष्ट्रपता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस जब हम नये भारत-सशक्त भारत को विकसित होते हुए देखते है तो प्रतीत होता है कि यह गांधी के ही सपनों का भारत बन रहा है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने गांधी की केवल मूर्तियां स्थापित की, लेकिन भावपा सरकार अपनी नीतियों में गांधी दर्शन को लागू कर रही है। गांधी के अहिंसा दर्शन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल देश में बल्कि दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। गांधी की अहिंसा ने भारत को गौरवान्वित किया है, भारत ही नहीं, दुनियाभर में अब उनकी जयन्ती को बड़े पैमाने पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी महानायक के रूप में ही नहीं, देवनायक के रूप में लोकतंत्र के मजबूत आधार एवं संकटमोचक है। संसद से लेकर सड़क तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और व्यक्ति से लेकर विचार बनने तक जीवन के हर नीति में, हर दृष्टिकोण में, हर मोड़ पर गांधी की व्याप्ति है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर नये भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां हमारी हर सोच में, हर क्रियाएं में, हर नीति में गांधी का होना यह दर्शा रहा है कि आज गांधी पूर्व सरकारों की तुलना में ज्यादा जीवंत बने हैं। मानवता के लिए एक मात्र सिद्धांत है कि सभी के लिए भलाई के काम में विश्वास करना।' मोदी सरकार सभी की भलाई के लिये काम करते हुए गांधी दर्शन को ही आगे बढ़ा रही है। मोदी का स्वच्छता मिशन गांधी की स्वच्छता सोच को ही आगे बढ़ाने का उपक्रम है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भी गांधी के नाम पर चल रही योजना है। भारतीय मुद्रा से लेकर शासन-प्रशासन के हर कार्यस्थल पर गांधी है। हम गांधी के संवाद और सहिष्णुता के सिद्धान्तों को अपनाते हुए युद्ध, आतंकवाद और हिंसा को निस्तेज बना रहे हैं। दलित-आदिवासियों को न्याय और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदत्त कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जुटे हैं। भारत माता, गौ माता और गंगा माता के सांस्कृतिक एवं धार्मिक चिन्तन को आगे बढ़ाते हुए गांधी की मूल अवधारणा को ही आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। आज गांव, गरीब और स्वराज में गांधी की ही सोच आगे बढ़ रही है कि आज भारत में लोकतंत्र की चाल, चेहरा और चरित्र बदला जा रहा है तथा आस्थाओं की राजनीति को बल देते हुए जाति-धर्म का उन्माद नियंत्रित किया जा रहा है। महात्मा गांधी, आंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय आज इसलिए भारत निर्माण की नई व्याख्याओं में सबसे आगे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम एवं सर्वधर्म सद्भाव का विचार आज सर्वाधिक बलशाली बन कर दुनिया के लिये आदर्श बन गया है। मानव ने ज्ञान-विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति की है। परन्तु अपने और औरों के जीवन के प्रति सम्मान में कमी आई है। विचार-क्रान्तियां बहुत हुई, किन्तु आचार-स्तर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन कम हुए। शान्ति, अहिंसा और मानवाधिकारों की बातें संसार में बहुत हो रही हैं, किन्तु सम्यक-आचरण का अभाव अखरता है। गांधीजी ने इन स्थितियों को गहराई से समझा और अहिंसा को अपने जीवन का मूल सूत्र बनाया। यदि अहिंसा, शांति और समता की व्यापक प्रतिष्ठा नहीं होगी तो भौतिक सुख-साधनों का विस्तार होने पर भी मानव शांति की नींद नहीं सो सकेगा। महात्मा गांधी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में नरेन्द्र मोदी हमारे सामने हैं, उनके प्रभावी एवं चमत्कारी नेतृत्व में हम अब वास्तविक आजादी का स्वाद चखने लगे हैं, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद की कालिमा धूल गयी है, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर भी नियंत्रण हो रहा है। इन नवनिर्माण के पदचिन्हों को स्थापित करते हुए हम गांधी को जीवंत बनाये हुए है, यही कारण है कि कभी हम स्कूलों में शोचालय की बात सुनते है तो कभी गांधी जयन्ती के अवसर पर स्वयं झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए मोदी को देखते हैं। मोदी कभी विदेश की धरती पर हिन्दी में भाषण देकर राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते है तो कभी मेक इन इंडिया का शंखनाद कर देश को न केवल शक्तिशाली बल्कि आत्म-निर्भर बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। नई खोजों, दक्षता, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा की रक्षा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन, श्रेष्ठ का निर्माण-ये और ऐसे अनेकों गांधी के सपनों को आकार देकर सचमुच लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता को सुदीर्घ काल के बाद सार्थक अर्थ दिये जा रहे हैं। हम देशवासियों के लिये अपूर्व प्रसन्नता की बात है कि गांधी की प्रासंगिकता चमत्कारिक ढंग से बढ़ रही है। देश एवं दुनिया उन्हें नए सिरे से खोज रही है। उनकी खोजने का अर्थ है अपनी समस्याओं के समाधान खोजना, युद्ध, हिंसा एवं आतंकवाद की बढ़ती समस्या का समाधान खोजना। शायद इसीलिये कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारों को पढ़ाया जा रहा है, उन पर शोध हो रहे हैं। आज भी भारत के लोग गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए अहिंसा, शांति, सह-जीवन, स्वदेशी का समर्थन करते हैं। गांधीजी आज संसार के सबसे लोकप्रिय भारतीय बन गये हैं, जिन्हें कोई हैरत से देख रहा है तो कोई कौतुक से। इन स्थितियों के बावजूद उनका विरोध भी जारी है। उनके व्यक्तित्व के कई अनजान और अंधेरे पहलुओं को उजागर करते हुए उन्हें पतित साबित करने के भी लगातार प्रयास होते रहे हैं, लेकिन वे हर बार ज्यादा निखर कर सामने आए हैं, उनके सिद्धान्तों की चमक और भी बढ़ी है। वैसे यह लम्बे शोध का विषय है कि आज जब हिंसा और शस्त्र की ताकत बढ़ रही है।

महाकुंभ पवित्र गंगा स्नान का महा-आयोजन

वैश्विक आध्यात्मिक गुरु बनने की महत्वपूर्ण पहल

संजीव ठाकुर

प्रयागराज में 144 वर्ष में आने वाले महाकुंभ के आयोजन ने यह तो सिद्ध कर दिया है की लगभग देश और विदेश के नागरिक इस महाकुंभ की पवित्र अवसर पर गंगा में स्नान करेंगे एवं पुण्य लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे। भारत के ही लगभग 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु इस पुण्य महाकुंभ में गंगा के संगम में पुण्य स्नान करने का लाभ उठाने वाले हैं। विश्व में इस अनूठे आयोजन को देखने विदेश के हजारों, लाखों पर्यटक गंगा में डुबकी लगाने लगातार प्रयागराज आ रहे हैं एवं पुण्य गंगा स्नान का लाभ उठा रहे हैं।

महाकुंभ के गंगा स्नान एवं गंगा पूजन ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल धार्मिक प्रशासक वैश्विक स्तर पर निर्विवाद नेतृत्व कर्ता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और इस महाकुंभ के आयोजन से यह भी स्थापित कर दिया है कि भारत का सनातन वैभव और सांस्कृतिक संपदा और परंपरा विश्व में स्थापित होने जा रही है भारत वैश्विक सनातनी गुरु बनने की ओर मार्ग प्रशस्त कर चुका है इस आयोजन ने पूरे विश्व को धर्म के प्रति आस्था एवं समर्पण से अभिभूत कर दिया है अब भारत को आध्यात्मिक विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मनुष्य को धर्म के साथ ही कर्म की वेदी पर अपने श्रम की की आहुति देनी चाहिए, जिससे मानवीय जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता के लिए मनुष्य को निरंतर कर्म,धर्म की प्रधानता रखकर संयम तथा मनोबल भी रखना होगा यद्दपाके अलावा मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास ना होकर उस पर नियंत्रण रख स्वामी बनने का प्रयास करना होगा तब सोची गई सफलता आपके सामने होगी। कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विनम्रता,संयम और साहस के साथ ऊंचा रखना चाहिए।अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के पल आपके सामने आएंगे।व निराशा, हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलबूते पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव, कठिन समय और विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैंव संकट का समय विषम परिस्थितियां जीवन के अलग-अलग पहलू हैं । इनसे जूझ कर जो मानव आगे बढ़ता है, वह उच्च मनोबल वाला साहसी व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विषमताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का मूल आत्मविश्वास, कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति को प्रेरणा ही सफलता दिलाने वाली होती है। मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से हार नहीं माननी चाहिए। उसे सदैव प्रयासरत रहकर परिश्रम तथा जुझारू पन से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार, हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से खड़ा होने एवं उस परिस्थिति मनोदशा से छुटकारा पाकर फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी परिस्थितियों को जीतने का साहस रखता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों से जूझना एवं टकराने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निर्भित होकर साहस, क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

सुरेश कुमार तनेजा
(शिक्षाविद् व साहित्यकार)

नमस्कार साथियों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के स्टार हैं शिक्षाविद् व साहित्यकार श्री सुरेश कुमार तनेजा जी। 15 सितम्बर 1968 को अलवर के गांव माणका ग्राम पंचायत माणका तहसील मुंडावर, जिला अलवर में जन्में शुरू से ही संस्कार और अपनी संस्कृति की मिट्टी से जुड़े रहे। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में शिक्षा हुई उसके बाद माध्यमिक शिक्षा खैरथल से उच्च शिक्षा आर्ट्स कॉलेज अलवर से करने के बाद बीएड जैन टीटी कॉलेज अलवर पोस्ट ग्रेजुएशन हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, वीएमओयू कोटा से एम.एड कर सरकारी सेवाओं में शामिल हुए। 20 वर्ष जालोर जिले में अपनी सेवाए दी। 5 वर्ष यशवन्त विद्यालय अलवर,वर्तमान में ऋंध सीरावासएु,अलवर में अपनी सेवाए दे रहे हैं। उपखण्ड स्तर पर सम्मानित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इन शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी आशु काव्य लेखन प्रतियोगिता में काव्यश्री का सम्मान भी मिला, इसके साथ ही विश्व हिंदी सृजन सागर मंच द्वारा श्रेष्ठ रचनाकार विषय पर वाणी कीमती आभूषण से नवाजा गया। विश्व हिंदी गौरव सम्मान-2025 भी इन्हीं की गोद में आया जहां विश्व हिंदी गौरव सम्मान से इन्हें नवाजा गया। बहुत मर्म के साथ साहित्य को बखूबी शब्दों में पीरोकर अमूल्य शब्दावली से लेखन करने वाले शानदार व्यक्तित्व है तनेजा जी। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

2025_029

बढ़ता राजस्थान

Suduko

8		7			4			6
5	6		3					7
		1	7	6		8	5	2
	7			3				5
	4			5		6		3
		3		2	1	7	8	4
		6			5	4	2	
	9	5	6					1
7			2	9				8

Ans_2025_028

4	2	9	1	6	8	3	7	5
7	3	1	5	4	9	2	6	8
8	5	6	3	7	2	1	4	9
9	7	5	8	3	1	4	2	6
6	1	8	9	2	4	7	5	3
2	4	3	6	5	7	9	8	1
3	9	4	7	8	5	6	1	2
1	8	2	4	9	6	5	3	7
5	6	7	2	1	3	8	9	4

कैसे खेलें

दर्न को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीपट्टा रोड खण्डवा,निवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिज्ञा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-भाईपाल निवाई, रोक मो.9414823448 अलवर कार्यालय-नेहाल सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 30 जनवरी 2025

ये दोस्ती...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद जिस तरह से खुद ट्रंप ने पीएम मोदी के अगले महीने वॉशिंगटन आने की घोषणा की, उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। कहीं न कहीं इससे इस संभावित यात्रा की अहमियत रेखांकित होती है। अच्छी बात यह भी है कि ट्रंप के खुलेपन के चलते द्विपक्षीय रिश्तों के अगले दौर को लेकर होने वाली बातचीत का अजेंडा काफी हद तक स्पष्ट हो गया है।

मोदी-ट्रंप मुलाकात पर नजरें

अवैध प्रवासी | ट्रंप अवैध प्रवासियों पर शुरू से मुखर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी इस पर वही करेंगे, जो सही होगा। जाहिर है, उनका मतलब भारत से आए अवैध प्रवासियों को वापस लेने से था। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत अवैध प्रवासन के पक्ष में नहीं है और सही तरह से पहचान हो जाने के बाद अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार है। इसलिए इस पर दोनों पक्षों में सैद्धांतिक सहमति है। यानी अब व्यावहारिक पहलुओं पर ही कुछ स्पष्टता लाने की जरूरत होगी।

ट्रंप की खास शैली | ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वह चाहते हैं भारत अमेरिका में बने रक्षा साजोसामान की खरीदारी बढ़ाए। फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप की ओर बढ़ने पर भी उनका जोर है। इसके अलावा रिपब्लिकन सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन और ब्राजील के साथ ही भारत का नाम लेते हुए टैरिफ लगाने की धमकी दी। अगर ट्रंप की अपनी खास शैली से अलग हटकर देखें तो ये सभी ऐसे मसले हैं, जिन पर पॉजिटिव नजरिए से बातचीत के जरिए सहमति बनाना मुश्किल नहीं होगा।

सहयोग की जरूरत | ट्रंप की बातों से भी यह स्पष्ट है कि दोनों देश एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत महसूस करते हैं। अगर ट्रंप चाहते हैं कि भारत, अमेरिका में बने रक्षा साजोसामान की खरीदारी बढ़ाए तो जाहिर है कि उससे होने वाले फायदे उनकी नजरों से छुपे हुए नहीं हैं। भारत ने भी फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप की ओर बढ़ने और खरीद बढ़ाने को लेकर खुलापन दिखाया है।

पॉजिटिव संकेत | ये संकेत काफी पॉजिटिव हैं। खुद ट्रंप भी यह समझते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हर देश ये बातें अपने राष्ट्रहित के आधार पर ही तय करता है। साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की बातचीत काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस बातचीत से पॉजिटिव नतीजों की उम्मीद ना करने की कोई वजह नहीं है।

साड्डी दिल्ली

याद है वह चुनाव

जग प्रवेश चंद्र देश के बंटवारे के बाद 1947 में दिल्ली आए थे। इस पराए शहर में वह 1952 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किशनगंज सीट से जीते। यानी, आने के पांच साल में ही विधायक बन गए। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक असरदार रहे एच.के.एल. भगत भी 1952 के चुनाव में कुचा हब्स खान सीट से चुने गए। पहली दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 27 मार्च, 1952 को हुआ था। तब विधानसभा में 48 सीटें थीं। कांग्रेस के पास डॉ. सुशीला नायर (देव नगर), चौधरी ब्रह्म प्रकाश (नांगलोई), मुश्ताक राय खन्ना (मंटोला), डॉ. युद्धवीर सिंह (चांदनी चौक), बैरिस्टर नूरुद्दीन अहमद (चावड़ी बाजार), गुरुमुख निहाल सिंह (दरियागंज), चिंता मणि (शाहदरा) और राघवेंद्र सिंह (दिल्ली कैंट) जैसे दिग्गज नेता थे। तब चुनाव प्रचार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के इर्द-गिर्द घूमता रहा। जनसंघ, जो 31 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, शरणार्थियों के अधिकारों पर सबसे मुखर था। कांग्रेस भी घबराई हुई थी, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता मीर मुश्ताक अहमद ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी।

खैर, कांग्रेस ने चुनाव में 37 सीटें जीतीं। हालांकि, जनसंघ से रीडिंग रोड (अब नई दिल्ली सीट) से अमीन चंद, गिरधारी लाल सलवान (झंडेवालान) और हेम चंद्र जैन (पहाड़ी धीरज) ने जीत हासिल की। ओबेरॉय होटल के मालिक एम.एस. ओबेरॉय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिविल लाइंस सीट से चुनाव लड़े और हारे थे। परिणामों के बाद लग रहा था कि डॉ. सुशीला नायर दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनेंगी, पर सीएम बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। गुरुमुख निहाल सिंह को स्पीकर चुना गया। डॉ. सुशीला नायर और डॉ. युद्धवीर सिंह दिल्ली वैबिनेट के सदस्य बने। डॉ. सुशीला नायर गांधीजी की शिष्या और उनकी निजी चिकित्सक भी थीं। मुख्यमंत्री बनते ही ब्रह्म प्रकाश ने दिल्ली सरकार के लिए केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। जब वह शांत नहीं हुए तो उन्हें पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। फिर गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति कभी नहीं दी।

- विवेक शुक्ला

एकदा

नियम तो नियम है

द्वितीय विश्वयुद्ध में फ्रांस का वर्साय राजमहल काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। यह भव्य महल, जिसे लुई 14वें ने बनवाया था, कला और शिल्प का अद्भुत नमूना था। युद्ध के कारण इसकी मूर्तियां जर्जर हो गई थीं, लकड़ी की फर्श कमजोर हो गई थी और सोने की परत भी अपनी चमक खो चुकी थी। अमेरिकी अरबपति जॉन डी. रॉकफेलर कला और संस्कृति के प्रेमी थे। जब उन्हें वर्साय महल की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने खर्च की परवाह किए बिना महल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। कुछ समय बाद, वह खुद यह देखने पहुंचे कि काम कितना आगे बढ़ा है। पेरिस पहुंचने के बाद जब वह महल के द्वार पर पहुंचे, तो रात हो चुकी थी और नियमों के अनुसार गेट बंद हो चुका था। वह चुपचाप लौट गए। जब उनके मित्रों ने सुना कि जिस महल के जीर्णोद्धार पर वह भारी धन खर्च कर रहे थे, उसे देखे बिना ही लौट आए, तो उन्होंने कहा, 'आप अपना परिचय दे देते, तो द्वारपाल तुरंत गेट खोल देता।' इस पर रॉकफेलर ने उत्तर दिया, 'नियम तो नियम होता है, उसका पालन होना चाहिए।' नियमों के प्रति यह निष्ठा भी रॉकफेलर की उन खूबियों में शामिल थी, जिनकी बदौलत उन्हें एक मिसाल के रूप में आज भी याद किया जाता है ।

Subrata Char

संकलन : ललित गर्ग

AAP के सामने एंटी-इनकंबेंसी की चुनौती है तो BJP को कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से जीत की आस

दिल्ली की पब्लिक किसका साथ देगी?

उमेश चतुर्वेदी

दिल्ली के चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की साख दांव पर लगी है। BJP और कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही पार्टियां चुनावी मुद्दे उछाल रही हैं, लेकिन इस बार मतदाता पिछले दो विधानसभा चुनावों की तरह मुखर नहीं है। इसलिए आंदाजा लगाना आसान नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।

बचाव में AAP | पिछले दो चुनावों की तरह यह चुनाव किसी एक मुद्दे पर चुनाव केंद्रित नहीं हो पाया है। पिछले दो चुनावों में भ्रष्टाचार का खात्मा और केजरीवाल की ईमानदारी के मुद्दे पर मतदान हुआ। इस बार किसी एक या दो मुद्दे पर चुनाव होता नहीं दिख रहा। लेकिन विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री निवास पर हुए खर्च के मुद्दे को जोरशोर से उछाल रही हैं। दरअसल, केजरीवाल ने अपने पहले चुनाव में गाड़ी, बंगला आदि लेने और शाहखर्ची को स्वीकार न करने को तरजीह दी थी। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में लगे दस एसी को मुद्दा बनाया था। इसलिए विरोधी दल उन्हें इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुफ्त की रेवड़ियों का वादा इस बार AAP के साथ BJP और कांग्रेस ने भी किया है।

यमुना की सफाई | चर्चा में रहे मोहल्ला क्लीनिक और शिक्षा के मॉडल को BJP और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। दोनों ही आरोप लगा रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर किए गए दावों में दम नहीं है। केजरीवाल ने सत्ता संभालते ही कहा था कि 2020 तक वह यमुना को साफ कर देंगे। लेकिन यमुना अब तक साफ नहीं हो पाई। BJP इसे पूर्वांचली मतदाताओं की अस्मिता से भी जोड़ रही है। दरअसल, पूर्वांचल का लोक त्योहार छठ अब दिल्ली का प्रमुख त्योहार बन चुका है और हर साल छठ व्रतियों को यमुना के गंदे जल में ही अर्घ्य देना पड़ता है।

लगातार पिछड़ती कांग्रेस | BJP 2013 से लेकर हर विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की जीतोड़ कोशिश करती रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, 2013 में वह अपनी रणनीतिक कमजोरियों की वजह से पिछड़ी। बाद में केजरीवाल की लोकप्रियता के सामने उसकी नहीं चली। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ, जिसका साथ दिल्ली की जनता ने पहले खूब दिया था। 1998 में 47.75% वोट और 52 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होकर तीन बार जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को 2013 में 24.6% वोट और आठ सीटें ही मिलीं। दो साल बाद हुए चुनाव में महज 9.7% और 2020 में 4.26% वोट के साथ वह फिसड्डी दलों की सूची में शामिल हो गई। दिल्ली में जितनी तेजी से कांग्रेस पिछड़ी, उतनी ही तेजी से AAP का ग्राफ बढ़ा। 2013 में उसे 29.5% वोट मिले, तो 2015 में 54.3% प्रतिशत वोट के साथ 67 सीटें मिलीं। 2020 में भी वह 53.57% वोट लेकर 62 सीटें जीतने में सफल रही।

क्या है चुनावी सीन
- केजरीवाल की छवि पहले सी नहीं
- BJP के पास CM का चेहरा नहीं
- कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं

मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल | इस बीच के दो लोकसभा चुनावों में एकतरफा जीत हासिल करने वाली BJP के लिए विधानसभा पर कब्जा ख्वाब ही रहा। पार्टी को 2013 में 33% तो 2015 में 32.3% वोट हासिल हुए। 2020 में BJP के वोट प्रतिशत में 6% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन वह जीत से कोसों दूर रही। दिल्ली के वोटरों ने केंद्रीय राजनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा तो जताया, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल उसकी पसंद बने रहे। शायद यही वजह है कि AAP बार-बार BJP के मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल उछाल रही है। इसके जरिए केजरीवाल खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं।

पूर्वांचली मतदाता | आज दिल्ली में करीब 22% पूर्वांचली हैं, जबकि 8% वोटर उत्तराखंड और हिमाचल के हैं। पूर्वांचली मतदाताओं को रिझाने के लिए केजरीवाल ने 11 तो BJP ने चार प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। BJP इस बार इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, शायद यही वजह है कि एक अलग पूर्वांचल मंत्रालय बनाने का वादा किया जा रहा है।

BJP को कांग्रेस से आस | वैसे, BJP की कामयाबी तीसरे दल की ताकत पर ज्यादा निर्भर करती है। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल को 12% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, जिसने पार्टी की जीत में भूमिका निभाई थी। अगले चुनाव में जनता दल अपने अंतर्विरोधों के चलते खत्म हो गया तो कांग्रेस को बढ़ने का मौका मिला। इस बार कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। अगर वह जनता दल की तरह 12-15% तक वोट हासिल करने में सफल हुई तो BJP की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

काश! वाल्मीकि मंदिर में ही रहते महात्मा

विवेक शुक्ला

बीते कई दिनों से कृष्ण विद्यार्थी आज (30 जनवरी को) राजघाटी के मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में होने वाली सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तैयारियां कर रहे हैं। राजघाट और गांधी स्मृति (पहले बिड़ला हाउस) से हटकर वाल्मीकि मंदिर में सैकड़ों आम जन पहुंचेंगे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने। इसी मंदिर के एक छोटे से कमरे में गांधी जी 1 अप्रैल, 1946 से 10 जून, 1947 तक रहे थे। इसकी देखरेख करते हैं कृष्ण विद्यार्थी। कहते हैं, जब तक गांधी यहां रहे, तब तक पूरी तरह से सुरक्षित थे। हमारा वाल्मीकि समाज दिन-रात उनकी देखरेख और रखवाली करता था। वह यहां प्रसन्न थे।

आखिरी आमद | यहां गांधी वाल्मीकि परिवारों के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनसे पंडित नेहरू से लेकर सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान तक सलाह-मशविरे के लिए आते थे। अमेरिकी लेखक लुई फिशर भी उनसे यहां मिलने आते। गांधी जब यहां रह रहे थे, नोआखाली और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। उन्होंने वाल्मीकि बस्ती छोड़ दी और निकल पड़े दंगे शांत कराने। उन्हें अपने मिशन में कामयाबी भी मिली। फिर गांधी जी 9 सितंबर, 1947 को दिल्ली वापस आए। वह शाहदरा स्टेशन उतरे। उन्हें लेने देश के गृह मंत्री सरदार पटेल और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर भी पहुंचे। गांधी जी रेलमार्ग से उस दिन अंतिम बार दिल्ली आए थे। पहली बार वह 12 अप्रैल, 1915 को यहां आए थे।

दिल्ली का चेहरा बदला | गांधी जी को शाहदरा रेलवे स्टेशन में बताया गया कि अब उनका नया ठिकाना होगा 5, अलबुर्कर रोड (अब तीस जनवरी मार्ग) का बिड़ला हाउस। अब उनके लिए वाल्मीकि मंदिर सुरक्षित नहीं है। वजह बताई गई कि दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही है। वाल्मीकि मंदिर में पाकिस्तान से आए कई शरणार्थियों को शरण भी दी गई थी। गांधी जी वाल्मीकि बस्ती छोड़ने से पहले कह कर गए थे कि वह वापस आएंगे और फिर से बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके दिल्ली से जाने और वापस आने के बीच भारत आजाद हो चुका था और लाखों हिंदू-सिख शरणार्थी आ चुके थे। मतलब कुछ महीनों में दिल्ली का चेहरा तेजी से बदल गया था।

कॉमन रूम

उपवास की रणनीति | बिड़ला हाउस में गांधी जी ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू करवा दी। वह दिल्ली में दंगे रुकवाने की कोशिशें करने लगे। 14 सितंबर, 1947 को गांधी इंदराज और मोतिया खान गए। दोनों जगहों पर दोनों संप्रदायों के लोगों ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पाकिस्तान से अपना सब कुछ खोकर आए हिंदू और सिख शरणार्थी हैरान थे कि गांधी जी कह रहे हैं, 'भारत में मुसलमानों को रहने का हक है।' जब दंगे नहीं रुके, तो उन्होंने 13 जनवरी, 1948 से अनिश्चितकालीन उपवास चालू कर दिया। यह उनके जीवन का अंतिम उपवास था। उनकी रणनीति सफल रही। दंगे थम गए। 18 जनवरी को उन्होंने उपवास तोड़ा।

पाहवा को माफी | दो दिन बाद 20 जनवरी, 1948 को बिड़ला हाउस में बम विस्फोट हुआ। अगले दिन अखबारों में छपा कि मदन लाल पाहवा ने पटाखा चलाया था। उसकी मंशा गांधी जी को चोट पहुंचाने की थी। उसी दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा कि जिस किसी ने भी यह कोशिश की थी, उसे मेरी तरफ से माफ कर दिया जाए। कृष्ण विद्यार्थी कहते हैं कि गांधी जी की हत्या उस जगह पर की गई, जिसे उनके लिए सुरक्षित बताया गया था। काश, वे हमारे पास होते तो मारे नहीं जाते।

क्यों नहीं दिया गया गोडसे का शव

नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधीजी प्रार्थना सभा में थे, जब गोडसे ने उन पर तीन गोलियां चलाईं। बापू की हत्या का मुकदमा 22 जून 1948 को दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। 10 फरवरी 1949 को जज ने गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों- गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद की सजा मिली।

नीतियों से नाराज | 14 फरवरी 1949 को सभी दोषियों ने पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। गोडसे ने अपनी फांसी की सजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन साजिश के आरोपों पर सवाल उठाए। उसने अदालत में कहा कि गांधीजी की नीतियां देश के लिए हानिकारक थीं, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने 'मर्डर ऑफ द महात्मा' किताब लिखी है। उनके मुताबिक, बापू की हत्या की साजिश रचने वालों का मानना था कि मुसलमानों के पक्ष में गांधी जी का झुकाव देश के लिए नुकसानदेह था।

पाकिस्तान की मदद | महात्मा गांधी ने नोआखाली दंगों में हस्तक्षेप किया था और 1948 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने के लिए अनशन पर बैठे थे। इन दोनों घटनाओं के चलते उनके प्रति नाराजगी और बढ़ गई थी।

भावुक भाषण | गोडसे ने 2 मई 1949 को अपील की सुनवाई के दौरान लंबा भाषण दिया। उसने आरोप लगाया कि गांधीजी की नीतियों के कारण देश का विभाजन हुआ। उसने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के कारण शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का महत्व कम आंका गया। उसने कहा, 'मैं जानता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और लोग मुझसे नफरत करेंगे। ... लेकिन मुझे यह भी लगा कि गांधीजी के बिना भारतीय राजनीति जरूर व्यावहारिक होगी, जवाब देने में सक्षम होगी, और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली बन सकेगी।' जस्टिस जीडी खोसला ने लिखा है कि गोडसे के भाषण का वहां बैठे लोगों पर गहरा असर हुआ। वे भावुक हो गए। अगर वे लोग ही जूरी होते, तो शायद गोडसे को दोषी नहीं ठहराते।

सख्त पहरे में फांसी | 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। हालांकि दोनों के शव उनके परिवार वालों को नहीं सौंपे गए। हमारे सहयोगी TOI में इस बारे में 13 और 16 नवंबर 1949 को दो खास रिपोर्ट पब्लिश हुई थीं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि फांसी के बाद प्रशासन ही शवों का अंतिम संस्कार करेगा।

एकता की खातिर | शव इसलिए नहीं सौंपे गए ताकि कट्टरपंथी तत्व उसके बहाने किसी तरह का प्रदर्शन न कर सकें। देश उस समय विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाए रखने की जरूरत थी।

टाइम मशीन

नो सर्टिफिकेट, प्लीज़

प्रणव प्रियदर्शी

मास्टर शेफ इंडिया 2023 में जज रह चुकीं गरिमा अरोड़ा अपनी पहेली का जाना-माना नाम हैं। हाल ही में उन्होंने गुड़गांव में नया थाई रेस्तरां शुरू किया है जो उनका दूसरा रेस्तरां है। बैंकॉक में वह पहले से ही एक रेस्तरां चला रही हैं। खास बात यह कि नया बिजनेस वेंचर उन्होंने तब शुरू किया, जब वह दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। उनकी प्रेग्नेंसी का यह आठवां महीना चल रहा है। उनका एक बेटा है जो 19 महीने का है। जाहिर है, घर और बिजनेस के अलावा उन्हें यात्रा में भी काफी समय देना पड़ता है। इस दौरान भी वह 18-18 घंटे रोज काम करती हैं। लेकिन उनके चेहरे पर इस बात को लेकर किसी तरह का तनाव या अफसोस नहीं दिखता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काम और घर से जुड़ी जिम्मेदारियां उनकी अपनी चुनी हुई हैं और दोनों ही उनकी पसंद का हिस्सा हैं। फिर भी वह किसी भ्रम में नहीं रहतीं। उनका कहना है कि वर्क-लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। करियर विमिन दोनों मोर्चों पर जूझती हैं और इस बात को लेकर परेशान रहती हैं कि वे दोनों के बीच बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। बकौल गरिमा जब आप काम पर होती हैं तो बच्चे की चिंता लगी रहती है और जब बच्चे के साथ होती हैं तो काम की चिंता हावी रहती है। दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकतीं। इसलिए बेहतर यही है कि परफेक्ट होने की चिंता छोड़ दें। गरिमा कहती हैं कि परफेक्ट कहलाए या हुए बगैर भी महिलाएं दोनों भूमिकाओं का निर्वाह कर रही हैं, जो अपने आप में सर्टिफिकेट है। उन्हें किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपनी ओर से खुद को मिलने वाले सर्टिफिकेट की भी नहीं।

गरिमा अरोड़ा

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ सुधार की जरूरत

29 जनवरी का संपादकीय 'खामियां हैं कानून में' पढ़ा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं भी हैं। निजता के अधिकार का हनन सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर। यह उन जोड़ों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है जो सामाजिक दबाव के कारण अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहते। प्रशासन को लिव-इन आवेदन खारिज करने का अधिकार देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। सरकार इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है, खासकर तलाक के प्रावधानों में।

प्रमोद द्विवेदी, ईमेल से

■ टीम इंडिया के गौरव

ICC ने भी स्वीकार किया कि जसप्रीत बुमराह विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भारत की राष्ट्रीय धरोहर हैं। पिछले दो दशकों में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान पाने वाले द्रविड़, तेंदुलकर, अश्विन और कोहली के बाद वह पांचवें भारतीय और पहले तेज गेंदबाज हैं। बुमराह की धारदार गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। वह सही मायनों में भारतीय टीम का गौरव हैं। इसलिए विरोधी टीमें उनकी प्रतिभा से ईर्ष्या करती हैं। बुमराह तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। लेकिन अभी वह चोटिल हैं। ऐसे में उनका चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए, ताकि प्रदर्शन पर कोई दाग न लगे और वह लंबे समय तक क्रिकेट की शान बने रहें।

बाल गोविंद, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अफजल वाली जेल में रहेगा
तहव्वुर- एक खबर।
- आपके कर्म आपको 'सही'
जगह पहुंचा ही देते हैं।

मीनाक्षी शर्मा

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

अहंकार को fine tune करेंगे तो वह प्रेम बन जाएगा

सुरक्षित गोस्वामी

कहा जाता है, अहंकार मत करो। लेकिन अहंकार को त्यागें कैसे? ध्यान देने वाली बात है। 24 तत्वों से मिलकर यह सृष्टि बनी है। इन्हीं में एक तत्व है अहंकार। अहंकार तो सृष्टि के फाउंडेशन में है। जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं हट सकता, उसी प्रकार अहंकार भी नहीं हट सकता। अहंकार वजूद है। यही बताता है कि यह मेरा शरीर है। छोटे बच्चे में अहंकार develop नहीं होता, इसलिए उसे अपने शरीर का भान नहीं होता। आपकी सुरक्षा आपका अहंकार करता है।

यह आपकी कार है। यह कौन बता रहा है? यह आपका अहंकार बता रहा है। अहंकार ही बताता है कि, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये मेरे वाले हैं। यहां तक अहंकार अच्छा है। लेकिन अच्छा तब तक है जब तक वह संतुलन में है। जब तक वह एक सीमा के अंदर है। जब अहंकार अति हो जाता है, तो वह बीमारी बन जाता है। कबीर दास जी ने भी कहा है- अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसलिए एक सीमा तक अहंकार अच्छा है और सीमा लांघने पर यह खतरनाक हो जाता है। जैसे हर चीज में अति होना खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं, अति सान्निध्य अवज्ञा पैदा करता है।

सर्दी के मौसम में आग कितना प्रिय लगता है। लेकिन उसके पास भी ज्यादा देर तक रहो तो वह जलाने लगती है। घरवालों के साथ लगातार रहते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं क्योंकि अवज्ञा होती है। अध्यात्म कहता है कि अहंकार अति हो जाता है तो वह बीमारी हो जाती है। फिर बीमार व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो अहंकार बुरा इसलिए हो गया, क्योंकि वह सीमा लांघ गया। गंगा नदी गुणों की खान है। उसमें दिव्यता है, ऊर्जा है। उसमें डुबकी लगाने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। लेकिन वही गंगा जब बाढ़ का रूप ले लेती है, अति विस्तार में चली जाती है, तो वह न स्नान करने योग्य भी नहीं रह जाती। वह विनाश करने लगती है।

अहंकार को फाइन ट्यून करने करके उसे संतुलित किया जा सकता है। जब यह fine tuned होता है, तो वही प्रेम बन जाता है। जैसे मक्खन को फाइन ट्यून करते जाओ, करते जाओ, एक समय आएगा जब वह घी बन जाएगा। अहंकार का एक स्वरूप है- मैं हूं और एक है, मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं, अहंकार का फाइन ट्यून स्वरूप है। जैसे भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- मैं ही सब जगह हूं। यह अहंकार नहीं। यही उस दिव्यता तक पहुंचा देगा।

हमारी जो central energy है, वह imbalanced होकर वह रही है। हम उसे योग के माध्यम से balance करते हैं। इस ऊर्जा का महासंतुलन तक पहुंचना ही मुक्ति है।

[illegible]

दैनिक जागरण
गौन कई अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है

महाकुंभ में अनहोनी

महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत ने पुनः यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर अपने देश में भारी भीड़ वाले आयोजनों में जानलेवा हादसे क्यों होते रहते हैं? प्रयागराज में मेला क्षेत्र में रात दो बजे के करीब भगदड़ हुई, इसलिए मच गई, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ आए। उनके दबाव से बैरीकेड टूट गई और फिर अव्यवस्था फैल गई। इसके चलते लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए और आपाधापी में उन्होंने उन लोगों को भी कुचल दिया, जो मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें से कुछ तो वहां सो रहे थे। जब प्रशासन इससे अच्छी तरह अवगत था कि मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तब उसने उन्हें संगम तट पर रुकने और सोने से क्यों नहीं रोका? जब श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ आनी थी, तब लोगों को संगम तट पर प्रतीक्षा करने और विश्राम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे भीड़ का अनावश्यक दबाव बढ़ता। प्रशासन को प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए थी कि श्रद्धालु आते जाएं और स्नान कर प्रस्थान करते जाएं। लगता है वह स्थिति का आकलन करने में चूक गया और इसी के चलते अनहोनी हो गई। इस तरह की अप्रिय घटनाएं केवल सुरक्षा प्रबंधों में किसी कमी के कारण ही नहीं होतीं। वे लोगों की ओर से अनुशासन का परिचय न देने के कारण भी होती हैं।

प्रायः आस्था के आवेग में लोग या तो संयम खो देते हैं या फिर सुरक्षा प्रबंधों की अनदेखी कर देते हैं और दुर्घटना से कई बार वहां भी, जहां कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है, जब लोग प्रशासन का सहयोग करें और उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहें। काश, महाकुंभ पहुंचे सभी श्रद्धालु यह समझ पाते कि मानव इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में उन्हें श्रद्धा भाव के साथ ही अनुशासन भाव का भी परिचय देना होगा। जब भी इसका अभाव व्याप्त होता है, भगदड़ जनित घटनाएं हो जाती हैं। यह पहले से संभावित था कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आठ-दस करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इतनी तो अनेक देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस तरह आसपास के जिलों से आ रहे वाहनों को रोकना पड़ा और श्रद्धालुओं से भरी ट्रेनों को रुक-रुक कर चलाना पड़ा, उससे यह भी रेखांकित हो रहा है कि जब भीड़ प्रबंधन एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य दिख रहा था, तब ऐसे किसी संदेश के प्रचार-प्रसार से क्यों नहीं बचा गया कि महाकुंभ में स्नान की सबसे पावन बेला मौनी अमावस्या ही है? यह राहतकारी तो है कि भगदड़ के बाद स्थितियां नियंत्रण में कर ली गईं, लेकिन जो अनहोनी हुई, उससे सही सबक सीखने अनिवार्य हैं।

स्मार्टफोन का दुरुपयोग

हर हाथ में मोबाइल ने हमारी कई मुश्किलों को आसान बनाया है। लेकिन, इसके दुरुपयोग से लोगों की जान तक जा रही है, जो गंभीर बात है। इस दिशा में शासन के साथ-साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि नुकसान को रोका जा सके। बिहार के हालिया दो उदाहरणों से समझें कि कैसे मोबाइल का दुरुपयोग भारी पड़ रहा है। मधेपुरा में कुछ युवकों ने एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार इसकी भनक जैसे ही युवती को लगी, उसने अपनी जान दे दी। हालांकि, लोक-लाज के डर से स्वजन कह रहे कि उनकी बेटी ने जान नहीं दी है, एक हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन, जिस गोपनीय तरीके से उसे दफना दिया गया, वह सारी कहानी बयां कर रहा। वहीं, दूसरी ओर बिहार के ही बाराहर में दो युवा तब मौत की आगोश में समा गए, जब वे तेज रफ्तार बाइक पर स्मार्टफोन से अपनी रील बना रहे थे। बाइक से दुर्घटना हुई और एक झटके में जिंदगी खत्म हो गई। रील के चक्कर ने उनकी रियल लाइफ खत्म कर दी। दोनों घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। शासन को तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था विकसित करनी जानी चाहिए जो आपत्तिजनक वीडियो के प्रसार को पकड़कर उस पर रोक लगा दे। अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस तरह के मामलों पर नजर रखने की जरूरत है। हम सभी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करें। विद्यालयों को भी चाहिए कि अब वे पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था में मोबाइल के प्रयोग को न्यूनतम करें। रील या इंटरनेट मीडिया का उनको चस्का न लगे। यह समस्या किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, वह पूरे देश की समस्या बन चुकी है। लिहाजा समेकित प्रयास से ही इस तरह की घटनाएं रुकेंगी।

तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए शासन-समाज दोनों को पहल करनी होगी

तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा

शिवकांत शर्मा

यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा

अवधेश राजपूत

जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका की फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जेनरेटिव एआइ का चैटबाट डीपसीक लांच किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डालर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैटजीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लोद जैसे चैटबाट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबाट बन बैठा। जब यह पता चला कि डीपसीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्नातक ने 60 लाख डालर से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया है तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं है कि डीपसीक अमेरिका के चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिव एआइ माडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तक में वह अमेरिकी माडलों की बराबरी पर ही है, पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लीगी और मामूली लागत से साल भर में ऐसा माडल तैयार कर दिखाया, जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने माडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीपसीक ओपन सोर्स माडल है यानी इसका प्रयोग, परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है।

ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिकी एआइ उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के माडल कम लागत पर बना सकें तो वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। इससे एक तो अमेरिकी एआइ माडलों की लागतों पर सवाल उठे, जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरे यह सवाल उठा कि सस्ते और किफायती चीनी माडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले माडल को कोई क्यों लेगा? इससे एआइ उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर सैलों के निर्माण पर हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा समान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है।

अमेरिका और यूरोप में अभी तक चीन की छवि नकल में पारंगत और सस्ता माल बनाने वाले देश की रही है। इसे बदलने और 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी बनने के लिए चीन ने 2006 में शोध और विकास यानी आरएंडडी की एक रणनीति बनाई थी, जिसे उसने अंजाम तक पहुंचाया। चीन अपना 2.5 प्रतिशत से अधिक बजट शोध एवं विकास पर लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में उसका योगदान 60 प्रतिशत हो। इस मामले में अमेरिका विश्व का अग्रणी देश रहा है, लेकिन अब चीन उससे बहुत पीछे नहीं है। अमेरिका शोध एवं विकास पर अपने जीडीपी का 3.4 प्रतिशत खर्च करता है तो चीन 2.41 प्रतिशत खर्च कर रहा है। भारत इस मामले में फिसड्डी है और जीडीपी का मात्र 0.64 प्रतिशत ही शोध एवं विकास पर खर्च करता है। यानी शोध एवं विकास पर चीन भारत से चौगुना बजट खर्च करता है। चीन का जीडीपी भी भारत से पांच गुना अधिक है, जिसके कारण शोध एवं विकास पर चीन का खर्च भारत से 20 गुना बैठता है और यह अंतर पिछले 20 साल से चल रहा है।

शोध एवं विकास पर विश्व में सबसे अधिक खर्च करने और आर्थिक विकास में उसका योगदान सुनिश्चित करने के कारण ही अमेरिका पिछले 50 वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना हुआ है। अब चीन उसी राह पर और भी सुनियोजित ढंग से चल रहा है। डीपसीक माडल के विकास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देने वाले चीनी इंजीनियर वेनफेंग ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा था, 'हम अक्सर सुनते हैं कि चीनी और अमेरिकी एआइ के बीच एक या दो साल का फासला है, पर असली फासला नकल और मौलिकता का है। वह नहीं बदला तो चीन हमेशा पिछलग्गू बना रहेगा और चीन हमेशा पिछलग्गू बना नहीं रह सकता।' वेनफेंग जैसे सैकड़ों अन्वेषक गुणवत्ता और लागत में पश्चिम को चुनौती दे सकने वाली तकनीक का विकास करने में जुटे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण, बिजली की कारें, कंप्यूटर गेम और एआइ माडलों में भी चीन की कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिका-यूरोप को व्यापार संरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है।

मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत और बढ़ गई है। इसके बिना न अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है और न अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देशों में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपना माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। इसलिए भारत को यदि अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में उसका योगदान अधिक से अधिक रहे। इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, जिन्हें आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्यवर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में टी-ढ्वाई करोड़ी लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

सबके हित की चिंता करे सरकार

राजीव सचान

सरकार को यह देखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे आएं

अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शनरत गिग वर्कर। प्रेट्र

दिल्ली में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक दलों में मुफ्त या रियायती सुविधाएं देने की घोषणा करने की होड़ मची है। सभी घोषणाओं को रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। कुछ घोषणाएं समय की मांग भी हैं, जैसे भाजपा का यह वादा कि वह दिल्ली के गिग वर्करों के लिए 10 लाख के जीवन बीमा और पांच लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करेगी। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन यह सुविधा तो सारे देश के गिग वर्करों को मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय जब गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि वे अपना जीवनयापन सही तरह और सम्मानजनक ढंग से कर सकें। ई कामर्स कंपनियों के सामान के साथ खाने-पीने की सामग्री की डिलिवरी करने वाले गिग वर्कर कहे जाते हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के रूप में काम करते हैं। उन्हें न तो कोई छुट्टी मिलती है और न ही अन्य सुविधा। जितना काम, उतना पैसा। काम नहीं तो पैसा नहीं। कंपनियां गिग वर्करों पर कम समय में सामान की डिलिवरी करने का दबाव तो बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन वे उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने को तत्पर नहीं। उनके काम के घंटे तय नहीं। यदि वे किसी घटना-दुर्घटना के शिकार होते हैं तो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं।

पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह सुनने को मिल रहा है कि वे गिग वर्करों के कल्याण और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाने वाली हैं, लेकिन अभी तक वे आश्वासन के स्तर पर ही हैं। देश में गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की एक रपट के अनुसार 2020-21 में गिग वर्करों की संख्या 77 लाख थी, जिसके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार को उनके हित की चिंता करनी ही चाहिए। जैसे गिग वर्कर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही निजी सुरक्षा कर्मी भी। एक आंकड़े के अनुसार देश में इस समय सवा करोड़ निजी सुरक्षा गार्ड हैं। उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हर कहीं और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी निजी सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त सुध नहीं ली जा रही है।

पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया था और चौकीदारों यानी निजी सुरक्षा गार्डों को संबोधित किया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हो सकी, जिससे उनकी कार्यदशाएं बेहतर होतीं। हालांकि सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनियों को पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन वे गार्डों को क्या सुविधाएं देती हैं, इसके लिए कोई ठोस नियम-कानून नहीं। देश में रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा कंपनियों की संख्या 23 हजार से अधिक है, लेकिन चंद ही सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश और वे सुविधाएं देती हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकतर निजी सुरक्षा कंपनियां गार्डों से 12 घंटे काम लेती हैं और उन्हें कोई छुट्टी नहीं देतीं। ये कंपनियां उनकी बदौलत पैसा भी उनके वेतन से काट लेती हैं। सरकारें चाहें तो आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं, जिससे सभी कंपनियां सुरक्षा गार्डों के काम के घंटे कम करने के साथ उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दें। हाल में दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि उनकी सरकार बनी तो राजधानी में सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन आखिर इससे निजी सुरक्षा गार्डों को कोई राहत कैसे मिलेगी? गिग वर्करों और निजी सुरक्षा गार्डों की अनदेखी यही बताती है कि किस तरह समाज का एक बड़ा तबका सामने होते हुए भी नीति-नियंताओं की आंखों से ओझल सा है।

हाल में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खुश कर दिया। इस वेतन आयोग का लाभ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी मिलेगा। पिछले सप्ताह यह खबर भी आई कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम को अधिसूचित कर दिया। यह योजना इसी एक अप्रैल से लागू होने जा रही है। नई पेंशन स्कीम को अनाकर्षक पा रहे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और एकीकृत पेंशन स्कीम लेकर आई। इस पेंशन योजना को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब अंतिम वेतन का करीब 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक पुरानी मांग पूरी कर दी, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन साढ़े सात हजार करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये है। यह सर्वथा अनुपयुक्त है।

सरकारें सबके लिए होती हैं। उन्हें जितनी चिंता सरकारी कर्मचारियों की करनी चाहिए, उतनी ही अन्य लोगों की भी। इसलिए और भी, क्योंकि अपने देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। सरकार को बजट या फिर उससे इतर यह देखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग सामाजिक सुरक्षा की दायरे में कैसे आएं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

वाद-विवाद

अध्ययन के दौरान बुद्धि विकास हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। उन्में पक्ष या विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि प्रतिभागियों के सोचने की परिधि में विस्तार हो। सामान्य जीवन में वाद-विवाद बुद्धि की कसरत से अधिक अहम की तुष्टि का विषय बन जाता है। वाद-विवाद का कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन और अहम को तुष्ट करने के लिए की गई बहस वास्तव में निरर्थक होती है।

विद्वान प्रायः युक्ति और तर्क की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। वे बोलते कम और सुनते अधिक है। यदि उन्हें कोई वाद-विवाद के लिए बाध्य भी करे तो वे शांतचित्त से संक्षिप्त उत्तर देकर उसमें बहुत समय तक उलझे नहीं रहते। उनके जीवन का लक्ष्य अस्थायी बहस जीतना नहीं, बड़े लक्ष्यों के लिए ऊर्जा बचाना होता है। अनावश्यक वाद-विवाद मनोदशा को नकारात्मक बनाता है।

बहस उत्तेजना को जन्म देती है। मन को चंचल करती है। विवेक को हर लेती है। कब एक स्वस्थ विचार-विमर्श तर्क-वितर्क के रास्ते चलता हुआ विवाद का रूप धारण कर लेता है, यह पता ही नहीं चलता। निरर्थक बहस से समय की बर्बादी होती है। संबंधों में कटुता आती है तथा चित्त में हलचल मच जाती है। अंत में प्रतीत होता है कि हाथ में कुछ आया भी नहीं।

अतः यदि कोई अकारण ही बहस करने के लिए बाध्य करे तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं होता। पात्र व्यक्ति देखकर ही उसके समक्ष तर्क रखने चाहिए, जो उन तर्कों को स्वस्थ बुद्धि से ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। वैसे भी मौन से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होता। तर्क-वितर्क का लक्ष्य बुद्धि को तीक्ष्ण करना होना चाहिए न कि दूसरे के मस्तिष्क पर बढ़त बनाना। अमेरिकी विद्वान राबर्ट विक्लेन ने कहा है कि चर्चा ज्ञान का आदान-प्रदान है, जबकि बहस अज्ञान का।

दिवंकल तोमर सिंह

लिव-इन रिश्तों में धोखाधड़ी पर लगाम

डा. मोनिका शर्मा

लिव-इन रिश्तों में महिलाएं अधिक ठगी जाती हैं, सो उन्हें बचाने की व्यवस्था की जा रही है

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। ध्यातव्य है कि यूसीसी नियमावली के प्रविधानों में विवाह और तलाक के पंजीकरण के साथ ही उत्तराधिकार से जुड़े नियम भी महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। इसी में लिव इन रिश्तों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने वाला पक्ष भी शामिल है। लिव-इन में रहने वाले या सहजीवन रिश्ते में साथ रहने की तैयारी करने वालों से जुड़े प्रविधान के तहत शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है।

यूसीसी कानून के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया के तहत जो जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के समने घोषणा करनी होगी। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की स्थिति में भी इस विषय में घोषणा करना आवश्यक है। मनचाहे रिश्तों की दायित्वबोध से जोड़ने वाले इन प्रविधानों के अनुसार उत्तराखंड का जो निवासी राज्य के बाहर रहता है, वह भी अपने जिले में अपने सह-जीवन संबंध के विषय में जानकारी दे सकता सकता है। यूसीसी में सहजीवन रिश्तों से जुड़ा एक अहम पक्ष यह भी है कि समान नागरिक संहिता नियमों के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है।

वस्तुतः बीते कुछ वर्षों में महानगरों में ही नहीं दूर-दराज के कस्बों और छोटे शहरों में भी सहजीवन संबंधों की ओर झुकाव बढ़ा है। दुखद है कि मनमर्जी से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। साथ रहने-जीने से जुड़ी तयशुदा नियमावली न होने से यौन शोषण, जालसाजी, घरेलू हिंस और एक दूसरे पर झूठे केस दर्ज करवाने की घटनाएं देशभर में हो रही हैं। बर्बरता से लिव इन साथी का जीवन छीनने के बावजूद तो स्पष्ट बताते हैं कि वर्षों के साथ में भी भावनात्मक धरातल पर कोई जुड़ाव नहीं होता। लिव इन के नाम पर झूठी पहचान बताकर बच्चियों और महिलाओं को भरमाने का खेल भी खेला जाता है।

उत्तराखंड में यूसीसी नियमों के अनुसार, अब उन लोगों का लिव-इन रिलेशनशिप भी वैध नहीं हो सकता जो अवयस्क हैं, पहले से शादीशुदा हैं या धोखे से ऐसे कर रहे हैं। धोखाधड़ी के कई मामलों में बर्बरता होने के बाद महिला के स्वजनों को उसके लिव इन में रहने की जानकारी मिलती है। ऐसे में 21 साल से कम उम्र के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियों का अपने स्वजनों को इस बारे में सूचित करने का नियम सुरक्षा से जुड़ा अहम पहलू है। असल में सह-जीवन संबंधों में महिलाएं ज्यादा ठगी जाती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक निर्णय में लिव-इन संबंधों को वैधानिक बनाने और सहजीवन संबंध स्थापित करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही जा चुकी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राजनीति को स्वच्छ बनाना आवश्यक

'शमिंदगी की बात' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही लिखा है कि दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए छह दिन की कस्टडी पैरोल मिलने से एक गलत परंपरा स्थापित होगी। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि देश में कोई आरोपित व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर कानून की इस खामी को सुधारना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेल में बंद किसी भी प्रकार के आरोपित को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता घटती है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध भी है। हमारे संविधान में चुनाव लड़ने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित हैं। अब इन प्रविधानों की समीक्षा करनी होगी, ताकि आरोपितों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। मतदाताओं को भी ऐसे प्रत्याशियों को नकारना चाहिए। भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह अपरिहार्य हो गया है।

budawanwalas55@gmail.com

देश के लिए घातक नकारात्मक राजनीति

विपक्षी दलों की वर्तमान राजनीति का स्तर काफी हल्का हो गया है। जबकि राजनीति में शुचिता, परिपक्वता के साथ एक-दूसरे नेता के प्रति मान-सम्मान राजनीतिक गहने होते हैं, ताकि राजनीति में ओछापन न पनपने पाए। जहां राजनीति स्तहीन और छिछली हुई, समझो राजनीति के मापदंड समाप्त हो चुके हैं। झूठ फरेब की राजनीति और अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। नेताओं के लिए मानव मूल्यों का महत्व व जनकल्याण केवल नारों में स्थापित हो जाता है। सत्ता हस्तांतरण येन-केन प्रकारेण एक मात्र ध्येय बन जाता है। वर्तमान में जनसाधारण का दिमाग तब शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब एक राज्य के नेताओं द्वारा दूसरे राज्य की सरकार पर नदी के पानी में जहर मिलाना और सामूहिक नरसंहार की योजना जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। यह पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना है। इन गंभीर आरोपों की उच्चस्तरीय सघन जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जनसाधारण का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। निश्चित ही ऐसे संगीन आरोप देश के संघीय ढांचे के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसा स्तब्ध कर देने वाला बयान ऐसे समय आया जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। निश्चित ही स्तरहीन, जहरीली और नकारात्मक राजनीति देश के लिए घातक ही सिद्ध होगी।

दीपक गौतम, सोनीपत।

शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य पर पाबंदी

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर) के संदर्भ में मध्य प्रदेश के परिणाम निराशाजनक आए हैं। आश्चर्य की बात है कि केंद्र और प्रदेश सरकार का संपूर्ण ध्यान स्कूली शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की ओर दिखा जा रहा है, बजट आवंटित किया जा रहा है, और शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं। फिर भी, ''असर'' के सर्वे में दूसरी और तीसरी कक्षा के 52 प्रतिशत छात्र-छात्राओं में अक्षर ज्ञान नहीं पाया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम अगर इस प्रकार से आते हैं, तो जिम्मेदारों को यह विचार करना होगा कि खामी कहां हो रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हो सकते हैं- शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाना। स्कूल के शिक्षकों को मतदाता सूची को अपडेट करने समेत निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न करना। वहीं, उन्हें शासन की कई योजनाओं का सर्वे घर-घर जाकर करना होता है। इस कारण छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए कक्षा में बैठे रह जाते हैं। यदि अच्छे परिणाम चाहिए, तो शिक्षकों से केवल पढ़ाई का कार्य लिया जाना चाहिए। दूसरा, छात्र-छात्राओं के पढ़ने के स्थान, यानी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिसे सुधारा जाना चाहिए। कई अन्य कारण भी हैं जिन कारणों से स्कूल में बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना होगा।

प्रदीप कुमार संघर्वे, शिक्षाविद, झाबुआ, एमपी।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्वप्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹ 2 अतिरिक्त।

****

40 प्रविचार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव में ऐसे 30 प्रतिशत प्रत्याशी चुनाव जीतकर रवाना थे, वहीं 2014 में इनकी संख्या 34 प्रतिशत और 2019 में 43 प्रतिशत थी, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार।

लालजी जायसवाल
सामाजिक मामलों के जानकार

आजकल

स्वच्छ छवि वालों को ही चुनाव लड़ने का अवसर

आगामी बुधवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के एक आरोपित एवं हालिया विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए छह दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। आरोपित अब प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार करेगा और स्वाभाविक है कि जनता के बीच स्वयं को वह निर्दोष भी बताने का प्रयास करेगा। लिहाजा चुनाव में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि जनता को केवल साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को ही चुनने का विकल्प मिल सके

प्रतीकात्मक

राजनीति से अपराध को समाप्त करने के विमर्श पर देश में निरंतर चर्चा होती रहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंगों के आरोपित एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिलहाल यह स्थिति इसलिए बन रही है, क्योंकि मौजूदा जन प्रतिनिधित्व कानून विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह विडंबना ही है कि कोई विचाराधीन कैदी वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। कानून की इस खामी का लाभ वे भी उठाते रहे हैं, जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। बता दें कि फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में करीब 50 लोग मारे गए थे। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप न केवल दंगों से जुड़े हैं, बल्कि गृह मंत्रालय के अधिकारी की हत्या से भी जुड़े हैं। चिंता की बात है कि भीषण दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता था, यदि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लेते कि संगीन धाराओं में आरोपित ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की छूट न मिले, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई हो। राजनीतिक दलों ने इस उचित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए।

लिहाजा इस दलील ने राजनीति के अपराधीकरण का दरवाजा खोलने का काम किया। कई ऐसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस सबके बाद भी आरोपित को चुनाव प्रचार की सुविधा मिल जाना घोर निराशा की बात है। निराशाजनक यह भी है कि दंगों के पांच साल बाद भी ताहिर हुसैन को सजा नहीं हो सकी। उचित होता कि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने के पहले यह साबित देखता और इसकी परवाह करता कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को चुनाव प्रचार करने की छूट देने से समाज में क्या संदेश जाएगा?

चुनाव सुधार गंभीर मुद्दा : वास्तविकता यह है कि चुनाव सुधार की मांग समय-समय पर उठती रही है और खासकर उस समय जब चुनाव नजदीक आए अथवा चुनावी प्रक्रियाओं के समय ज्यादा ही चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने की बात की जाती रही है। मालूम हो कि कुछ दिन बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन मसलों का हल चुनाव से पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया जाता? इसका उत्तर यह कदापि नहीं है कि चुनाव आयोग शक्तिहीन हो चुका है, आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं और वह निष्पक्षता से काम भी कर रहा है। लेकिन कुछ ठोस से यह देखा जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो सदैव चुनाव सुधार की बात की जाती है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां सदैव इसमें असहयोग और विरोध ही प्रकट करती रही है। शायद यह कयास लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चुनाव सुधार से राजनीतिक दलों को यह भय सता रहा होगा कि उनके मनमानी और आपराधिक संलिप्तता तथा धन का अथाह उपयोग पर रोक लग जाएगा। जैसे भी भारत में होने वाले चुनावों में बढ़ी मात्रा में धन की आवश्यकता एक कड़वी सच्चाई है। इसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित होती रही है और जिसका शायद ही कभी पालन किया जाता है।

चुनावी प्रक्रिया में एक गंभीर मुद्दा भड़काऊ भाषणों का भी है जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए चुनाव आयोग को कठोर होना होगा। आज के नेता युवाओं को भड़काने के लिए उग्र नारे देते हैं जिससे वे चर्चा में बने रहें। वास्तव में यह हाल की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। सवाल उठता है कि क्या नेताओं की जुबान अनजाने में फिसलती है या फिर जानबूझ कर जुबान फिसलाई जाती है। बहरहाल, मालूम हो कि नेताओं की जुबान का फिसलना जिसे हम लोग बिवादित बयान भी कहते हैं, वह जुबान जानबूझ कर चर्चा में रहने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। लिहाजा, अब ध्यान रखना होगा कि जब हम स्वयं को दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र कहते हैं, तब ऐसे राजनीतिक अपरिपक्वता को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्थान देना कितना सही होगा?

चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध : अपराधी करार दिए जा चुके जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना राजनीति के निरपराधीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः निरंतर राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह कदम उचित ही कहा जा सकता है। यह भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक निवारक कारक की तरह कार्य करेगा और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से बचेंगे। राजनीति में स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का प्रवेश होगा। इससे जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।

जहां तक आजीवन प्रतिबंध का सवाल है तो यह भारतीय राजनीति को स्वच्छ करने की दिशा में एक दूरगामी कदम साबित हो सकता है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस कदम के प्रविधानों का दुरुपयोग न हो। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 40 प्रतिशत वर्तमान सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून को सख्त करने से राजनीति के अपराधीकरण की समस्या दूर नहीं होगी। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई कमजोरियां हैं। लिहाजा कमजोर आधार पर सजा को बढ़ाने से सरकार को प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगाने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करने का ही अवसर मिलेगा।

विचाराधीन कैदियों को मिले कानूनी सहायता

सुमन कुमार
अधिवक्ता और नीतिगत मामलों के जानकार

मानव अधिकार की रक्षा से जुड़े विषयों पर आए दिन चर्चा होती रहती है। ऐसे में जेल के अंदर वर्षों से बंद विचाराधीन कैदी के संदर्भ में बात करना स्वाभाविक है। खासकर जब भारत में जेलों में बंद लगभग दो-तिहाई कैदी विचाराधीन श्रेणी में हैं। वस्तुतः विचाराधीन कैदी उन्हें कहा जाता है जिन्हें उन आरोपों के लिए अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है जिनके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। माना जाता है कि उन्हें 'न्यायिक हिरासत' में रखा गया है, परंतु आमतौर पर उन्हें जेलों में रखा जाता है। विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ा है, ताकि वे गवाहों को प्रभावित न कर सकें।

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो) के अनुसार, देश की जेलों में चार लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जो कुल कैदी के दो-तिहाई से भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को देश के सभी जिलों में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को शामिल करते हुए विचाराधीन समीक्षा समितियों की स्थापना के लिए राज्य अधिकारियों और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में विमर्श यह है कि कानून की प्रक्रिया द्वारा अपराध स्थापित होने से पहले कोई सजा कितनी होनी चाहिए? जेल में बंद विचाराधीन कैदी की अवधारणा दोषसिद्धि से पहले की सजा के समान है, क्योंकि उसे संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में हमें विचाराधीन कैदियों और दोषियों के बीच के अंतर को समझना होगा। विचाराधीन 'पीड़ितों' के बीच कहीं न कहीं आर्थिक दुष्टिकोण भी एक कारक है। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या काफी बढ़ी है, जिसका एक पक्ष आर्थिक, बेरोजगारी और सामाजिक है। एकमात्र तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है आरोपी द्वारा उचित संदेह से परे किए गए कृत्य की स्थापना। विचाराधीन कैदियों के लिए उपलब्ध निष्पक्ष प्रणाली में कैसे मजबूती और त्वरित न्याय मिले इस पर सोचना होगा।

विचाराधीन कैदियों के पास त्वरित सुनवाई के साथ-साथ निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें जेल से अदालत में स्थानांतरित करते समय हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि इसके लिए वैध कारण न हो। अपने मामले में सहायता के लिए कानूनी सहायता का वे लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके पास इसका लाभ उठाने का साधन नहीं है, तो वे अदालत में आवेदन करके मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वर्तमान में जेल प्रणाली में एक बड़े सुधार की गुंजाइश है। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बुनियादी मानवीय मानकों तक लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक अपराध में सजा काटने की अवधि के अनुसार एक वर्गीकरण होना चाहिए और कैदियों को उसी के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। देश में कानूनी सहायता की समीक्षा के लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना होनी चाहिए जो विचाराधीन कैदियों को न्याय के दायरे में ला सके और उन्हें न्याय का लाभ मिल सके।

खरी-खरी

आज मौसम बड़ा बेईमान है...

शरद उपाध्याय

आज मौसम बड़ा बेईमान है... जब भी यह गीत सुनता हूं तो लगता है कोई गड़बड़ होने वाला है। मौसम पर आजकल भारतीय राजनीति की छाया पड़ गई है। पता ही नहीं चल पाता कि कब कौनसी करवट ले बैठे। जिस तरह हम किसी राजनीतिज्ञ के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी तरह मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्लोबल वार्मिंग की भीषण गर्मियों की चेतावनी के बाद जमती ठंड मुझे हैरान कर रही है। मुझे मौसम विज्ञानियों पर तरस आता है। मौसम विज्ञानी और मौसम, दो असमान विचारधाराएं हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, वो भविष्यवाणी कुछ करते हैं, पर हो कुछ और जाता है।

पहले मैं मौसम विभाग की बात को बहुत गंभीरता से लेता था। जब भी वो कहता, 'जोरदार बारिश की संभावना है, बरसातो, छाते से लैस होकर निकलता था। पत्नी कहती, 'ये क्या, आसमान तो साफ है।'

मैं मन ही मन हंसता। मैं साहसी योद्धा की तरह निकल जाता। बस में, दफ्तर में लोगों की फब्तियां सुनता। पर हिम्मत नहीं हारता कि कभी तो बरसेगा। पर कमबख्त सुबह से शाम तक एक बूंद भी नहीं टपकती।

बाद में मौसम विज्ञानी भी दयनीय भाव लिए बयान दे देता था। इसमें हमारी क्या गलती है। हमने तो बिल्कुल सही आकलन किया था, पूरा माप-तौल सही था।

बेचारा वह भी क्या करे, मौसम भी नैतिकता की पटरी से उतर गया है। मैं देख रहा हूं, विज्ञानी ग्लोबल-वार्मिंग की चेतावनी दे रहे हैं। वे गर्मी को लेकर परेशान हैं, भयभीत हैं। इतना खतरनाक वर्णन करते हैं कि गर्मी से सारी बर्फ पिघल जाएगी।

लेकिन लोग हक्के-बक्के हैं। चारों तरफ ठंड ही ठंड है। आदमी कपड़े पहने रहा है, गरम चीजें खा रहा है और ठंड से कांप रहा है। ठंड जो है, हड्डियों तक को जमा देने वाली है। रोज मैं उठता हूं, मौसम विज्ञानियों को स्मरण करता हूं। घरवालों से कहता हूं, 'चिंता मत करो। ठंड अब जाने ही वाली है, विज्ञानी कह रहे थे, बर्फ बस पिघलने वाली है। हमारे अस्तित्व को खतरा है। लेकिन फिर सोचता हूं, मौसम का क्या? वह तो बेईमान है...

पोस्ट

मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई वह दुखद है, लेकिन जिस शीघ्रता से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया, वह सराहनीय है।
मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को संभालने का दायित्व सिर्फ शासन-प्रशासन का ही नहीं है। आपसी सहयोग और मानवता की भावना से एक-दूसरे का सहयोग भी करें।
शिवमी गुलजार है@Gulzar_sahab

वीवीआरपी दर्शन का मामला हमारे मंदिरों और धार्मिक स्थलों में एक बीमारी की तरह फैल गया है। यह महाकुंभ में भी दिखा। भगदड़ दुखद खबर आई। वक्त की पुकार है वीवीआरपी मुक्त कुंभ, वीवीआरपी मुक्त मंदिर।
सचेत उपाध्याय@sanket

घरेलू क्रिकेट की नाक रणजी ट्राफी में बड़े-बड़े सितारा खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से मुकाबलों में नई जान आ गई है। दर्शकों में उत्साह बढ़ा है। कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर की टीम ने सितारों से सजी मुंबई को उसके मैदान पर ही मात दी थी।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या महाकुंभ पर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान होगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या वीजा तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका की पछाड़ सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दुर्घटना जैसे हुई टूट पड़े सब गिद्ध,
ताक लगाए थे सभी यही हो रहा सिद्ध।
यही हो रहा सिद्ध ताकते रहते मौका,
इक गलती पा जाय मारते मिलकर चौका।
पटे पड़े थे घाट न चाहे कोई हटना,
सचमुच है दुर्भाग्य कुंभ की यह दुर्घटना।
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

फिर बच जाएंगे भ्रष्टाचार के मगरमच्छ

भ्रष्टाचार अब ऐसा मुद्दा बन गया है, जिस पर कोई न तो बात करना चाहता है, और न ही इस विषय में किसी की रुचि बची है। पहले भ्रष्टाचार की बात आती थी तो चौतरफा बिहार के चारा घोटाले की ही बात की जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे निकल गया है। आयकर विभाग के नोटिस और जांच की बात हो तो मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारियों की संख्या ही सबसे अधिक होगी। प्रदेश कैडर के ही आइएएस रहे अरविंद जोशी और टीनू जोशी भ्रष्टाचार के मामले में बखूबी होने वाले पहले अधिकारी रहे हैं। इसके बाद न जाने कितने घोटाले हुए, सैकड़ों करोड़ का पोषण आहार घोटाला, ई-टेंडर घोटाला, आयुष्मान घोटाला से लेकर व्यापमं घोटाले जैसी दर्जनों कहानियां हैं, जो प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं।

अभी एक बिल्डर राजेश शर्मा के यहां आयकर के छापों में एक मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की पोल खुली, उसने भी अपनी काली कमाई बिल्डर के व्यवसाय में लगा रखी थी। कई अन्य ब्यूरोक्रेट्स भी इस गिरोह में शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। प्रदेश में लोकायुक्त संगठन ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां छापा मारा तो कई करोड़ की संपत्ति मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके घर से 54 किलो सोना और दस करोड़ की नकदी एक गाड़ी से बाहर भेज दी गई। स्पष्ट है कि बिना मिलीभगत के यह संभव नहीं है। आगे देखिए, इसमें प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री होती है और वह भी छापेमार कार्रवाई करती है। लोकायुक्त संगठन से आगे वह कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज हासिल कर लेती है। इसके बाद दोनों एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश करती हैं। 41 दिनों तक सौरभ शर्मा दोनों एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहता है और जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। सौरभ तब गिरफ्तार किया जाता है, जब वह अदालत में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। उसके अचानक प्रकट होने की घटना भी गले नहीं उतर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा मामला मैनेज होने के बाद ही सौरभ बाहर आया है। इसकी कई वजह भी हैं।

लोकायुक्त पुलिस की अभिरक्षा में सम्मान से विदाया गया सौरभ शर्मा। नईदुनिया

सौरभ तो एक ऐसी छोटी मछली है, जिसे कभी भी कोई भी दबोच सकता है। दरअसल, अब इस मामले को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि सौरभ के पीछे जो राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के चेहरे छिपे हैं, कोई भी उन्हें सामने नहीं लाना चाहता है। मध्य प्रदेश का ही दुर्भाग्य कहें, जब भी बड़े घोटाले हुए, सभी सरेकदमेश को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश का हनीट्रैप मामला भी इसी में से एक था, जिसमें कई मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, लेकिन वह भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी विचार का प्रश्न है। न्यायालय में भी दोषी बचा लिए गए और हनीट्रैप कर ब्यूरोक्रेट्स से करोड़ों रुपये वसूलने वाली महिलाओं के खिलाफ प्रकरणों में भी वह धीरे-धीरे बरी हो रही हैं। अब यह कौन सा नया समीकरण क्यों बन रहा है, समझा जा सकता है। इस हनीट्रैप मामले का जिक्र इसलिए किया गया, क्योंकि इसमें भी दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। एक मुख्य सचिव ऐसे थे, जिन्होंने आइएएस अधिकारियों के 'अंश्रेश क्लब' में हनी ट्रैप की दागी महिला को मेंबर बना दिया था। उसी क्लब में जाकर वह महिला अपने शिकार फंसाती थी। खैर अभी बात भ्रष्टाचार के 'परिवहन' यानी सौरभ शर्मा की चल रही है।

जिस नाटकीय घटनाक्रम में सौरभ की गिरफ्तारी हुई, उससे साफ हो गया कि अब मामले में पानी डालकर सारे मगरमच्छ को बचा लिया जाएगा। इसकी कई वजहें हैं। सौरभ शर्मा के जमानत आवेदन में स्पष्ट लिखा है कि 54 किलो सोना, गड़ी करोड़ों की नकदी से उसका कोई संबंध नहीं है। लोकायुक्त और ईडी ने जिस घर में छापा मारकर करोड़ों की नकदी और 50 से अधिक बेनामी संपत्ति बरामद की है, उससे भी सौरभ ने पल्ला झाड़ लिया। आशय साफ है कि सौरभ को मगरमच्छों ने बचाने का आश्वासन दे दिया है, इसलिए अब वह किसी भी बड़े मगरमच्छ का नाम और उसका राज नहीं बताएगा। इसी धरोसे पर सौरभ अपने बिल से बाहर निकला है। मध्य प्रदेश की सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे मसलों पर उसके कमजोर रुख से केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब कोई बिहार का नाम नहीं लेता है, बल्कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। बेहरा कमेटी की जो रिपोर्ट कई दशकों से धूल खा रही है, उसे निकालने का समय तो चला गया, लेकिन अब नए सिरे से एक ऐसी कमेटी बनाने का समय आ गया है, जो सिंडीकेट- माफिया के साथ या भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त लोगों को संरक्षण देने वाले अधिकारी-नेताओं की जानकारी जुटाए। अब भी यदि यह कदम नहीं उठाया गया तो भ्रष्टाचार के इस नए गिरोह को रोकना मुश्किल होगा।

हिमाचल प्रदेश डायरी

रेरा को सेब बांटने की क्या जरूरत

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी चर्चा में है। इसलिए नहीं कि भू संपदा नियमन में कोई क्रांति आ गई है। इसलिए कि 10 लाख रुपये के सेब, लगभग देशभर में सरकारी कोष से उपहारस्वरूप भेजे गए। यह उस संस्थान की बात है, जिसके किसी निर्णय से आप रुष्ट हों तो याचिका दायर करने के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा। यानी एचपी रेरा की एपीलेट अथारिटी हरियाणा रेरा है। हिमाचल प्रदेश में याचिका सुनने का प्राधिकरण छोटे प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय संकट की दलील देकर नहीं बनाया गया। वित्तीय संकट का नाम लेकर हिमाचल प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान को छलनी किया गया। क्या पड़ोसी राज्य की उसी संस्था को याचिका सुनने का अधिकार देकर इस विचार की ताकत नहीं दी गई कि वित्तीय संकट और बढ़े तो कल को और महत्वपूर्ण कार्यालय बंद कर पड़ोसी राज्यों के कार्यालयों से काम चलाया जाए?

जी! चर्चा में उपहार के सेब हैं। हाल में एचपी रेरा के पहले अध्यक्ष पद पर कार्यबल पूरा करके गए, राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी श्रीकांत बालदी कहते हैं कि 'सेब दिए तो क्या हुआ। अपने संबंधियों को नहीं दिए, अधिकारियों को दिए।' अच्छी बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल सरकार, वीरभद्र सिंह सरकार और कुछ समय जयराम ठाकुर सरकार में वित्त सचिव और कालांतर में मुख्य सचिव रहे अधिकारी स्पष्ट हैं कि सेब देकर कुछ गलत नहीं किया। ठीक बात है, उपहार संस्कृति तो व्याप्त है ही। सेब लोकपाल, केंद्र सरकार के कार्यालयों और कई प्रदेशों के मुख्य सचिवों तक गए। किंतु हैरत सेब की उन पेटियों पर होती है जो राजस्थान की ओर थोक में दौड़ीं। काश, सेब की पेटियां बोल पातीं कि वे कि किस महफिल की गुलजार करने का दायित्व लेकर गईं। राजस्थान से हिमाचल प्रदेश का संबंध पौंग बांध से भी है... जहां का पानी रेगिस्तान को शीतल करने का प्रयत्न करता है, किंतु हिमाचल प्रदेश के हिस्से में विस्थापन तो आता है, अनुसगढ़, घड़साना धूप और कांटों पर भी अधिकार इतने दशकों तक नहीं मिला।

शायद, कभी वह प्रयोजन, हित और आवश्यक-आवश्यकता सार्वजनिक हो कि राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग सचिव और मुख्य सचिव, राजस्थान शिक्षा विभाग का हिमाचल प्रदेश रेरा के साथ कौन सा संबंध है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो संस्था अपने विरुद्ध याचिका सुनने के कार्यालय का खर्च नहीं उठा सकती, वह सेब खरीद के लिए क्यों तैयार हुई। एचपीएमसी से हुई यह खरीद सरकारी दस्तावेजों का अभिन्न अंग है। एचपीएमसी वही निगम है, जिसका जूस चेन्नई, कोलकाता और मुंबई रेलवे जंक्शन समेत देश के कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी मिलता था। अब यह निगम भी सहोदर निगमों और बोर्डों की तरह घाटे में है। लेकिन उसे तो एचपी रेरा के रूप में ग्राहक ही नहीं, गुणग्राहक भी मिला। अब यह भी समने आना चाहिए कि सरकारी पैसे से हुई यह खरीद आडिट में आपत्ति की पात्र बनी या नहीं। दोनों ही स्थितियों में सरकार को सक्रिय होना चाहिए।

बात दस लाख रुपये के सेब भेजने की नहीं, वरिष्ठ नौकरशाहों की उस अधिकार की भावना की है, जिसके अंतर्गत चाय का कप भी सरकारी धन से पीया जाना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। आखिर वेयरएज आई... आइएएस... कोई शब्द हैं। उपहार की प्रकृति है कि वह एक दिशा में जड़ या स्थिर नहीं रहता, वह किसी न किसी रूप में पलट कर आता है। एचपी रेरा को यह बता कर जनता का भ्रम दूर करना चाहिए कि जिन स्थानों पर उपहार भेजे गए हैं, हिमाचल प्रदेश को उनसे क्या लाभ हुआ। जिस प्रदेश का वित्तीय संकट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा हो, वहां लंबा समय बिल को देखते रहे अधिकारी के नेतृत्व में यह सब होना, प्रश्नों को अवसर देता है।

आइएएस भारत की वह शानदार सेवा है जो अब भी अधिसंख्य का सपना है। पहले दिन से प्राप्त वाहन और चालक को छोड़ देना चाहिए। यह वही हिमाचल प्रदेश है, जहां कुछ सस्ते आइटसोर्स पर हैं, जितनी पगार तय है, उससे कम पर हस्ताक्षर करते हैं। जहां पटवारी ही नहीं, चपरासी बनने के लिए भी इंजीनियर और पीएचडीधारक तक कतार में होते हैं कि आइटसोर्स के ठेंक से बच जाएं।

अच्छी बात यह है कि शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने माना है कि रेरा का काम अन्य राज्यों के अधिकारियों को सेब बांटना नहीं है। जांच के लिए भी कहा है। क्योंकि दूध में पानी अधिक है, इसलिए मुहावरा बदलते हुए आशा है कि जांच में सेब का सेब और संतरे का संतरा अवश्य किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी का शिमला स्थित कार्यालय। जागरण

और साथ ही सुरक्षाकर्मी सेवाकाल तक बने रहते हैं। इस सेवाकाल के कानूनन समाप्त होने के बाद यानी बादशाहत का एक दौर समाप्त होने के बाद, वहीं छोटी-छोटी जागीरों और सूबेदारियों के पीछे भाग कर प्रासंगिक बने रहना और ऐसे अनुरोधों का स्वीकार होना हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश ही नहीं, स्वयं व्यक्ति के हित में भी नहीं होता। वह कौन सा ऊंचा स्तंभ होता है और कितना ऊंचा होता है जिस पर बैठ कर प्रश्नों को समाप्त करने के बजाय, उनकी पैदावार की जाती है। शायद अखिल भारतीय सेवाएं यह नहीं बताती कि जब भूमिका समाप्त हो जाए, रंगमंच

****